



The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च ३, १९४९/फाल्गुन १२, १९२०

No. 45]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 1999/PHALGUNA 12, 1920

वित्त पंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1999

सं. एफ. 15(1)-बी (डी)/99.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित

किया जाता है:--

655 GI/99 - 1

बजट 1999-2000

वित्त मंत्री

श्री यशवन्त सिन्हा

का

भाषण

27 फरवरी, 1999

भाग क

मान्यवर,

मैं वर्ष 1999-2000 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

प्रस्तायना

2. स्वतंत्रता के बाद पहली बार संसद में सभी राजनैतिक दलों के उत्साहपूर्ण सहयोग से मेरे लिए 5 बजे सायंकाल बजट प्रस्तुत करने की दीर्घकाल से चली आ रही अंग्रेजी हुकूमत की परम्परा छोड़ देना संभव हुआ है। आज एक नई शुरूआत हो रही है जब मैं 20वीं सदी का अंतिम बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि यही केवल एक नई शुरूआत नहीं है बल्कि इस बजट में अनेक नई बातें हैं।

आर्थिक परिप्रेक्ष्य

- 3. नब्बे का दशक असाधारण परिवर्तनों का साक्षी रहा है। इसका शुभारंभ केन्द्रीय रूप से आयोजित अर्थव्यवस्था से हुआ और इसका समापन गंभीर संकट से जूझती बाजार अर्थव्यवस्था से हो रहा है।
- 4. 1998 का वर्ष विश्व में अमूतपूर्व अशांति का वर्ष रहा है। पूर्व-एशियाई वित्तीय संकट ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अर्थ-व्यवस्थाओं को काफी नुकसान पहुंचाया और यह अन्य देशों में भी फैल गया। जापान में मंदी की स्थिति बनी रही और अगस्त, 1998 में गंभीर संकट ने रूस को आक्रांत किया। जनवरी, 1999 तक इसका प्रभाव ब्राजील तक फैल गया जहां अत्यधिक पूंजी असंतुलन तथा मुद्रा का तेजी से मूल्यह्रास हुआ। विश्व के उत्पादन की वृद्धि 2 प्रतिशत से भी नीचे गिर गई, विश्व व्यापार की वृद्धि में तेजी से कमी आई, वस्तुओं की कीमतें तेजी से गिर गई, मुद्राओं पर गंभीर आघात पहुंचा और विकासशील देशों में पूंजी प्रवाह में तेजी से गिरावट आई।
- 5. भारत में, हमें भी पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद हम पर लगी आर्थिक पाबंदियों की अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ा। यद्यपि हम इन घटनाओं से अप्रभावित नहीं रहे फिर भी इन गंभीर चुनौतियों के प्रभावों के सामने जिस तरह से हम डटे रहे वह एक संतोष की बात

- है। प्रतिकूल आर्थिक वातावरण के बावजूद वर्ष 1998-99 में हमारे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछले वर्ष 5 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गई। हमारे किसानों ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है। वर्ष 1998-99 के प्रारंभ से ही हमने अपने विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में 23 फरवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार 2 विलयन अमरीकी डालर की वृद्धि की है और हमने विदेशी मुद्रा बाजार में अनुचित अस्थिरता को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटा 1997-98 में 1.6 प्रतिशत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 1.4 प्रतिशत पर होने का अनुमान है। यद्यपि वर्ष के दारान मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी फिर भी हम इसे अब 5 प्रतिशत से नीचे लाने में सफल रहे हैं। इन सभी का विस्तृत ब्यौरा कुछ दिन पूर्व संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा में दिया गया है।
- 6. फिर भी, यह सभी देखते हुए हम संतोष करें ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे समक्ष अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों चुनौतियां गंभीर बनी हुई हैं। केन्द्र और राज्य दोनों का राजकोषीय और राजस्व घाटा अभी भी बहुत अधिक है और यह ब्याज दर कम करने, निवेश और वृद्धि में तेजी लाने, मुद्रास्फीति को रोकने, प्राथमिकता के लिए संसाधन उत्पन्न करने, निर्ब्याज व्यय की आवश्यकताओं और निर्यात बढ़ाने की हमारी क्षमता को क्षति पहुंचा रहे हैं।
- 7. प्रत्येक वर्ष हमारी निरन्तर चिन्ताओं एवं प्रयत्नों के बावजूद, हम गरीवी एवं बेरोजगारी की समस्याओं पर एक सीमित सफलता ही प्राप्त कर सके हैं। इस क्षेत्र में सरकार की विभिन्न स्कीमों में लक्षोन्मुखता की कमी रही है। सेवा प्रदायक प्रणालियों को किफायती एवं समुदाय पर आधारित बनाए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक विकास के लाभ बड़े पैमाने पर गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को मिलने चाहिए जिसके लिए उन्हें पूरी तरह समर्थवान बनाने की आवश्यकता है। मुझे आशंका है कि इसके बिना हमारी योजना दिशाविहीन हो जाएगी।
 - 8. अतः इस बजट की व्यापक कार्यनीति निम्नलिखित 6 प्रकार की है:
 - मींवी याजना में विनिर्दिष्ट आधार पर राजस्व और राजकोषीय घाटा कम करने की मध्यायधिक प्रक्रिया शुरु करना, जो उत्पादक निवेश और वृद्धि के लिए अधिक संसाधन मुक्त करेगी तथा मुद्रारफीति रोकेगी।
 - जत्पादकता एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अप्रत्यक्ष करों में बड़े सुधार करना।
 - सभी मुख्य क्षेत्रकों में आर्थिक सुधारों को गहन और व्यापक बनाना तथा हमारे किसानों, विनिर्माताओं, व्यापारियों और सेवा प्रदान करने वालों की क्षमता और सृजनात्मकता प्राप्त करने के लिए आंतरिक उदारीकरण बढ़ाना।
 - बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करना, निर्यातों को पुनः गित प्रदान करना तथा. विकास को आगे बढ़ाने के लिए घरेलू साधनों में तेजी लाना।
 - ' ज्ञान पर आधारित उद्योगों को सुदृढ़ करना और इस प्रकार नई सहस्त्राब्दि की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करना। अंतिम परन्तु महत्वपूर्ण कार्यनीति
 - मानव विकास के लिए सरकारी कार्यक्रमों जिनमें खाद्य सुरक्षा, स्वारथ्य देखरेख, शिक्षा, रोजगार एवं आश्रय प्रदान करना शामिल है, को पुनः सशक्त एवं दिशा निर्देशित करना है। इनका मुख्य उद्देश्य गरीबों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दूसरे पिछड़े वर्गों को समर्थवान बनाना होना चाहिए।

कृषि और ग्रामीण विकास

9. इस वर्ष के विकास निष्पादन ने एक बार फिर हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व

को उजागर किया है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मैं एक बहुआयामी कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव करता हूं।

- 10. जल के संबंध में जो कृषि का प्राण हैं, मैं निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूं:
 - प्क राष्ट्रीय कार्यक्रम के ढांचे के अंदर अनेक प्रकार के जल संभरण, विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है, जलसंभरण विकास का राष्ट्रीय आंदोलन, स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन को संपोषित करता है तथा ग्राम पंचायतों, स्थानीय स्व- सहायता दलों और गैर सरकारी संगठनों की सिक्रिय भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक आधारभूत संरचना का सृजन करता है। इसके लिए 3 वर्षों के भीतर 100 प्राथमिकता वाले जिलों को शामिल करने के लिए "नाबार्ड" के साथ एक जलसंभरण विकास निधि स्थापित की जाएगी। केन्द्रीय सरकार "नाबार्ड" को आवश्यक समतुल्य सहायता उपलब्ध कराएगी। यह भूमिहीनों और गरीबों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए आय के साधन उत्पन्न करेगी।
 - * त्विरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का लक्ष्य राज्यों को समतुल्य सहायता प्रदान करते हुए चालू सिंचाई परियोजनाओं को जल्दी पूरा करना है। तथापि, अधिकांश राज्यों में जल की दरें यहां तक कि पूर्ण प्रचालन और अनुरक्षण लागतें भी पूरा नहीं करतीं। महंगी सिंचाई परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और अनुरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र राज्यों को और अधिक वित्तीय सहायता देगा, तािक कम से कम प्रचालन और अनुरक्षण लागतें पूरी करने के लिए उनकी जल दरों को युक्तिसंगत बनाया जा संके।
 - गल प्रबंधन में किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वृद्धिकारी जल दर संग्रहण से संबद्ध सभी पंजीकृत जल प्रयोक्ता संघों को एकमुश्त प्रबंधन आर्थिक सहायता तथा 3 वर्ष की प्रारंभिक अविध के लिए आवर्ती सहायता केन्द्र द्वारा दी जाएगी। इससे राज्यों के अपने अंशदान की अनुपूर्ति होगी।
- 11. अधिकतम प्रभाव के लिए जल एवं ऋण का प्रवाह साथ-साथ होना चाहिए। पिछले वर्ष मैंने बैंकिंग क्षेत्रक से कृषि क्षेत्रक को ऋण प्रदान करने में सुधार के लिए अनेक उपायों की घोषणा की थी। मुझे इस सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि चालू वर्ष में कृषि क्षेत्र के लिए सांस्थानिक ऋण प्रवाह ने 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है जो पिछले वर्ष 31,698 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष लगभग 38,000 करोड़ रुपए है। मैं कृषि तथा ग्रामीण ऋण प्राप्ति को सुधारने के लिए निम्नलिखित और उपाय करने का प्रस्ताव करता हुं:
 - राज्य सरकारों की ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) का एक महत्वपूर्ण स्कीम के रूप में आविर्भाव हुआ है। पिछले वर्ष मैंने आर.आई.डी.एफ.-IV के अधीन बैंकिंग क्षेत्रक से 3000 करोड़ रूपए का आवंटन करने की घोषणा की थी। मैं इस स्कीम को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। आर.आई.डी.एफ.-V की संचित निधि बढ़ाकर 3500 करोड़ रूपए की कर दी जाएगी। अदायगी की अवधि भी पांच से बढ़ाकर सात वर्ष की जा रही है। ग्राम-स्तर की आधारभूत संरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों, स्व-सहायता दलों और अन्य पात्र संगठनों को ऋण प्रदान करने के लिए आर.आई.डी.एफ. को व्यापक बनाया जाएगा।
 - पिछले वर्ष की गई घोषणा के अनुरूप सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरु की गई है। ये कार्ड किसानों को किफायती रूप से समय पर ऋण प्रदान करते हैं। अभी तक छः लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मैं

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों से इस स्कीम का दायरा बढ़ाने के लिए अनुरोध कर रहा हूं ताकि आगामी वर्ष में बीस लाख किसान इस स्कीम से फायदा उठा सकें।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ और पुनर्गित करने के लिए प्रारंभ किए गए सुधार जारी
 रखे जाएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूंजीकरण के लिए 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है।
- ' विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक रोजगार उत्पन्न करने की लघु उद्यमों की अत्यधिक क्षमता है। 'नाबार्ड' और 'सिडबी' ने लघु उद्यमों को निधियों प्रदान करने के माध्यम के रूप में स्व-सहायता दलों और गैर सरकारी संगठनों को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्कीमें शुरु की हैं। पिछले बजट में की गई पहल के बाद 'नाबार्ड' द्वारा 10,000 के लक्ष्य की तुलना में 1998-99 में लगभग 15,000 स्व-सहायता समूहों को शामिल करने की संभावना है। मैं 'नाबार्ड' और 'सिडबी' से इस दिशा में अपने प्रयासों को दुगुना करने और इस वर्ष के दौरान कम से कम 50,000 स्व-सहायता दलों को शामिल करने का अनुरोध कर रहा हूं।
- खाद्य और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के लिए ऋण प्राप्ति बढ़ाने के लिए इस क्षेत्रक को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करना प्राथमिकता क्षेत्रक हेतु ऋण प्रदान करना माना जाएगा।
- 12. आज हमारे पास बहुत कमजोर फसलोत्तर भंडारण और विपणन आधार सुविधा है। इससे अत्यधिक राष्ट्रीय क्षित होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए मैं शीत-भंडारों और गोदामों के निमाण हेतु एक नई ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूं। यह स्कीम, जो 'नाबार्ड' की सहायता से कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, 12 लाख टन की अतिरिक्त शीत भण्डारण क्षमता सृजित करेगी और अगले वर्षों में मौजूदा इकाइयों को 8 लाख टन के भण्डारण तथा आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी। हम प्याज मंडारण की 4.5 लाख टन क्षमता सृजित करने का भी प्रस्ताव रखते हैं। यह सदन, विशेषकर, मुख्य विरोधी दल प्याज के लिए हमारी विशेष चिंता को स्वतः समझ सकते हैं।
- 13. कृषि योग्य भूमि की चकबंदी न होने से भूमि का उत्पादक उपयोग कम हो पाता है। कुछ राज्य भूमि सुधार के इस महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान देने में पीछे रह गए हैं। इस दिशा में सुधारों की गित तेज करने के लिए केंद्रीय सरकार यह कार्य करने वाले राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करेगी।
- 14. उर्वरक के कारगर वितरण और प्रयोग की एक समस्या, बुआई कार्य के समय इसकी मांग और उपलब्धता में असमानता की है। इस समस्या से निपटने के लिए मैं अप्रैल और मई में कृषि कार्य की मंदी के महीनों के दौरान सहकारी समितियों से उर्वरक उठाने हेतु किसानों के लिए प्रोत्साहन छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।
- 15. अवक्रमित और बंजर भूमि के विकास की चालू स्कीमों को पुनः अनुकूल बनाया जाएगा तािक स्थानीय स्व-सहायता दलों और भूमिहीन गरीबों विशेषकर अनुसूचित जाित, अनुसूचित जनजाित तथा पिछड़े वर्गों को प्रत्येक गांवों में ऐसी भूमि विकसित करने और उपयोग करने की सुविधा मिल सके। संपूर्ण कार्यक्रम ग्राम पंचायतों की मुख्य भूमिका के साथ उनकी प्रबंध भागीदारिता पर आधारित होगा। वर्ष 1999-2000 के दौरान हम उन राज्यों में जो बराबरी का अंशदान करने के लिए तैयार हैं, परीक्षण के आधार पर यह स्कीम प्रारंभ करने के लिए कुल 50 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करेंगे।

ग्रामीण उद्योगीकरण क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

16. रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, ग्रामीण आय बढ़ाने और कृषि उद्योग संबंधों को

सुदृढ़ बनाने के लिए ग्रामीण औद्योगिकीकरण महत्वपूर्ण है। अभी तक इस पर अनेक सरकारी एजेंसियां कार्य करती आ रही हैं। तथापि, निचले स्तर पर इन कार्यक्रमों का प्रभाव कम ही रहा है। हमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कार्यों को एकीकृत करना चाहिए और सिक्रय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तदनुसार, ग्रामीण उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 100 ग्रामीण समूह स्थापित करने के लक्ष्य से मैं ग्रामीण उद्योगीकरण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूं। यह ग्रामीण दस्तकारों और बेरोजगार युवकों के लाभ के लिए किया जा रहा है। अन्ततः इससे शहरी और ग्रामीण असमानताएं कम होंगी। लघु उद्योग विकास संगठन इस कार्यक्रम का समन्वय करेगा। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के पास उपलब्ध विपणन संबंधी आधारभूत ढांचे का इस प्रयास में इष्टतम उपयोग किया जाएगा। अगर के.वी.आई.सी. इस प्रयोजन के लिए अपना ब्राण्ड नाम दे सका तो इससे ग्रामीण औद्योगिक उत्पादों के विपणन में बहुत सहायता मिलेगी। प्रस्तावित ग्रामीण समूह का विस्तार सारे देश में किया जाएगा। उच्च क्ष जच्च क्षमता तथा पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के बीच उचित संतुलन रखा जाएगा।

राष्ट्रीय मानव विकास संबंधी पहल (एन.एच.डी.आई.)

17. स्वतंत्रता के पचास वर्षों के पश्चात् भी भारत में मानव विकास का स्तर अधिकांश अन्य देशों से पीछे है। मानव विकास का मूल आधार समाज के सुविधा विहीन वर्गों को अधिकारिता प्रवान करना है तािक वह विकास प्रक्रिया का लाभ उठा सकें। मेरी दृष्टि में इस अधिकारिता में पांच बुनियादी आवश्यकताएं अर्थात् भोजन, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, शिक्षा, रोजगार और आश्र्य सुलभ कराना शामिल है। एक दशक के अंदर देश की संपूर्ण आबादी के लिए इन्हें उपलब्ध कराने के प्रति हम कृत-संकल्प हैं। लोगों पर आधारित विकास के इस प्रयास के साथ हम 'सुधारों मैं सुधार' के प्रधानमंत्री के फरमान का कार्यान्वयन करेंगे।

खाद्यः लिक्षित सार्वजिनक वितरण प्रणाली को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न कीमतों के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसके पर्यवेक्षण एवं कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों की अधिक भागीदारी के साथ लिक्षत सार्वजिनक वितरण प्रणाली को उचित रूप से सुदृढ़ किया जाएगा तािक इसके समुचित विस्तार को सुनिश्चित किया जा सके और कारगर बनाया जा सके।

परन्तु इस लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ऐसे गरीब वरिष्ठ नागरिक पर्याप्त रूप से नहीं आते जिनकी अपनी आमदनी नहीं है और गांव में उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैं 1999-2000 में "अन्नपूर्णा" नामक एक नई स्कीम आरंभ करने का प्रस्ताव करता हूं। "अन्नपूर्णा" स्कीम ऐसे सभी गरीब वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान करेगी जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं परन्तु इस समय उसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इस स्कीम से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या इस समय राज्य के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ग्राम पंचायतों को इसका व्यापक प्रचार करने के बाद ऐसे व्यक्तियों का पता लगाना, उनकी सूची तैयार करना और उसे प्रदर्शित करना होगा।

स्वास्थ्य-देख रेखः स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना और सेवा का विस्तार और सुधार प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विशेष कार्य योजना में निर्धारित मुख्य लक्ष्य हैं। जहां अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के लिए व्यापक नेटवर्क सृजित किया गया है, वहीं अपर्याप्त सामुदायिक भागीदारी और पर्यवेक्षण के कारण इन सुविधाओं का उनकी क्षमता से बहुत कम उपयोग हुआ है। हमारा लक्ष्य विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों में स्वास्थ्य देखरेख, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास और संबद्ध क्षेत्रों में मौजूदा कार्यक्रमों को एकीकृत करना और सहक्रियात्मक बनाना और उपलब्ध

संसाधनों का प्रयोग करना है ताकि प्रत्येक परिवार की प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख और परिवार कल्याण सेवाएं दोनों तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित हो सके। केन्द्र सरकार ऐसी ग्राम पंचायतों को निधियां प्रदान करेगी जो अपने-अपने क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं स्थापित करने के लिए अपने अंशदान के साथ आगे आती हैं। संबंधित राज्य सरकार से भी समान सहायता प्राप्त होगी।

शिक्षाः लोगों को अधिकार प्रदान करने के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुलभता महत्वपूर्ण है। कई राज्यों ने शिक्षा गारंटी स्कीमों के अपने संबंधित मॉडलों से काफी सफलता दर्ज की है। मैं राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा गारंटी योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव करता हूं। इसका उद्देश्य प्रत्येक वासस्थान जिसमें 1 किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय न हो, में एक प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था करना होगा। प्रारंभ में, स्थानीय समुदाय विद्यालय परिसर प्रदान करेंगे और किसी स्थानीय व्यक्ति का अंशकालिक शिक्षक के रूप में चयन करेंगे। शिक्षण सामग्री और अन्य सहायता केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी जबिक ग्राम पंचायतें कम से कम दो वर्ष तक विद्यालय चलाने के लिए स्थानीय लोगों से नकद और वस्तु रूप में अंशदान जुटाएंगी। विद्यालय के दो वर्ष तक सफलतापूर्वक चलने के बाद इसका स्थायी आधार पर उन्नयन किया जाएगा। नौंवी योजना के आगामी तीन वर्षों के दौरान ऐसे कम से कम 1.8 लाख विद्यालय कार्यरत हो जाएंगे। मौजूदा केन्द्र-प्रायोजित शिक्षा स्कीमों के अधीन उपलब्ध संसाधन इस महत्वपूर्ण पहल को समर्थन देने के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। इस पहल से ग्रामीण गरीबों किए शिक्षा प्राप्त करने का एक अवसर मिलेगा। उन्हें समर्थवान वनाने की दिशा में यह पहला एवं स्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है।

रोजगारः इस समय, कई स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार स्कीमें चल रही हैं। ग्रामीण गरीबों के लिए आय-प्राप्ति के अवसर उत्पन्न करने के लिए इन स्कीमों की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार पंचायतीराज संस्थाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के साझे सिद्धांत के साथ एक चहुमुंखी कार्यनीति का अनुपालन करेगीः

जवाहर रोजगार योजना की वर्तमान स्कीम यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित की जाएगी कि ग्रामीण आधारभूत संरचना मृजित करने के लिए सभी निधियां ग्राम पंचायतों के अधिकार में रखी जाएं। उन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन से निर्माण कार्य निष्पादित करने की शक्ति सहित वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वयन का एकमात्र प्राधिकार होगा। इस संशोधित स्कीम को ग्राम समृद्धि योजना कहा जाएगा।

रोजगार आश्वासन स्कीम का मजदूरी रोजगार कार्यक्रम अन्य चुने गए प्रतिनिधियों के परामर्श से जिला परिषदों द्वारा निर्णय किए जाने वाले निर्माण कार्य के चयन से जिला/ प्रखण्ड स्तर पर कार्यान्वित किया जाएगा। रोजगार अश्वासन स्कीम इस समय संपूर्ण देश में कार्यरत है। हम स्थानिक श्रमिक निष्क्रमण से प्रभावित क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देंगे।

ग्राम पंचायत संवीक्षा के लिए ग्रामसभा और जनता को उपलब्ध एक तैयार रोजगार रिजस्टर रखेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरी रोजगार स्कीम के अधीन रखी निधियों का व्यय चुनी गई पंचायती राज संस्थाओं की सिक्रय भागीदारी से किया जाता है, यह प्रस्ताव किया जाता है कि सामान्य कार्यविधि के अनुसार जहां 80 प्रतिशत निधियां कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को जारी की जाएंगी वहां शेष 20 प्रतिशत निधि केवल तभी जारी की जाएगी अगर राज्य में चुनी गई और अधिकार प्राप्त पंचायती राज संस्थाएं मौजूद हैं।

गरीब ग्रामीणों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रमों की बहुलता के स्थान पर 'स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना' नाम से एकल कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायतों की और अधिक भागीदारी होगी। इससे इस कार्यक्रम को अमल में ला रही एजेन्सियां स्थानीय लोगों की जरूरतों को और अधिक माफिक ढंग से पूरा कर सकेंगी।

इन स्कीमों से अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और बेरोजगारों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ मिलेगा।

आश्रयः 1997-98 की शुरूआत में लगभग 140 लाख ग्रामीण आवासों की कमी होने का अनुमान था, जिसमें आश्रयहीन परिवारों और वे परिवार जिनके पास केवल कच्चे घर हैं, शामिल थे। सरकार की प्राथमिकता नवीं योजना के अन्त तक सभी आश्रयहीन गरीब परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने की होगी। गरीब परिवारों के कच्चे घरों को पक्का करवाने का कार्य दसवीं योजना के दौरान पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, घर, साफ-सफाई और पेयजल की एकीकृत व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हमारा एक व्यापक 'समग्र आवास योजना' शुरु करने का प्रस्ताव है जिसमें इन्दिरा आवास योजना सहित मौजूदा कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा।

18. राष्ट्रीय मानव विकास अभिक्रम आबादी के सबसे कमजोर तबकों को सामर्थ्यवान बनाने और देहाती जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। इसमें गांव और शहर के बीच की खाई को अधिकाधिक कम किया जा सकेगा। इस अभिक्रम की कारगरता मुख्यतः इस बात पर निर्भर करेगी कि एक निर्वाचित निकाय के रूप में ग्राम पंचायत किस हद तक कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। मानव विकास को आयोजना का सबसे अहम उद्देश्य बनाने के साथ ही लोकतन्त्र में विकेन्द्रीकरण लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के हमारे संकल्प की पुष्टि की दिशा में मेरा यह प्रस्ताव है कि वर्ष 1999-2000 को 'ग्राम सभा वर्ष' के रूप में घोषित किया जाए।

आवास

- 19. अब हम शहरी क्षेत्रों में आवास की बात पर आते हैं। हमने पहले ही आवास निर्माण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी भूमि (हदबन्दी एवं विनियमन) अधिनियम के निरसन सित महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आवास निर्माण हेतु ऋण की प्राप्ति में सुधार लाने के लिए मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:
 - * आवास बंधकों के लिए प्राथिमक और गौण बाजार का विकास करने हेतु यह आवश्यक है कि पुरोबन्ध और सम्पत्ति के हस्तान्तरण सम्बन्धी मौजूदा कानूनी उपबन्धों को सरल बनाया जाए। मेरा प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में संशोधनों के जिरए आवास क्षेत्रक में पूरोबन्ध कानूनों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं।
 - ' आवास वित्त कम्पनियों को सुदृढ़ करने के लिए मैं गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों पर अर्जित आय पर कर व्यवस्था में परिवर्तनों का प्रस्ताव करूँगा ।
 - अावास क्षेत्रक को बैंकिंग निधियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंकं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह देगा कि वे अपनी वृद्धिशील जमाराशियों का 3 प्रतिशत तक आवास वित्त के लिए उधार दें ।
 - * राष्ट्रीय आवास बैंक स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण आवास वित्त स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके लिए मैंने गत वर्ष एक लाख आवासीय इकाइयों के लक्ष्य की घोषणा की थी। इस स्कीम से मिले संतोषजनक परिणामों से उत्साहित होकर मैं वर्ष 1999-2000 के दौरान इस लक्ष्य को 25 प्रतिशत बढ़ाकर 1.25 लाख आवासीय इकाइयां करने का प्रस्ताव करता हूँ।

- राष्ट्रीय आवास बैंक ने एक स्कीम का प्रस्ताव किया है जिसमें छोटे उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरों में कमी करना शामिल है। यह स्कीम उन शहरों में लागू रहेगी जहां शहरी भूमि (हदबन्दी और विनियमन) अधिनियम लागू नही है। हम राष्ट्रीय आवास बैंक को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सहायता मुहैया कराएंगे। इस स्कीम के ब्यौरे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा घोषित किए जाएंगे।
- 20. शहरी क्षेत्रों में आवास विकास का कार्य काफी हद तक शहरी सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। हमारी बहुत सी नगरपालिकाएं इस समय वित्तीय रूप से इतनी कमजोर हैं कि वे बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं। वित्तीय बाजारों में इन निकायों की साख को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, मेरा प्रत्येक वर्ष जारी म्यूनिसिपल बांडो की एक सीमित मात्रा को कर मुक्त दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव है। थोड़ी देर बाद मैं आवास निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दूरगामी कर प्रस्तावों की घोषणा करूंगा।

उद्योग एवं आधारभूत सुविधाएं

- 21. मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ते हुए एकीकरण और विश्वव्यापी बाजारों में व्याप्त अपरिहार्य अनिश्चितताओं के संदर्भ में भारतीय उद्योग जगत के लिए पिछले दो वर्ष कठिन रहे हैं। परन्तु हमें इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि किस तरह भारतीय उद्योग ने इन कठिन चुनौतियों पर जीत हासिल की है और अनेक क्षेत्रों जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी और औषधियों में विश्व श्रेणी के आला उत्पादों का उत्पादन किया है। नयी चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में कॉरपोरेट और औद्योगिक पुनर्सरचना की प्रक्रिया अपरिहार्य हो चली है। इस संक्रमण में मदद के लिए मैं महत्वपूर्ण कर प्रस्तावों की घोषणा करूंगा जिससे कम्पनियों के विलयन और एकीकरण में आसानी हो सके।
- 22. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की पुनरीक्षा कर उसमें संशोधन किया जाएगा ताकि हमारा ध्यान मूल रुप से उद्योग के विनियमन के बजाय उसके विकास की ओर जा सके।
- 23. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम प्रतिस्पर्धात्मक कानूनों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम के पिरप्रेक्ष्य में कितपय क्षेत्रों में पुराना पड़ चुका है। हमें अपना ध्यान एकाधिकारिक प्रणालियों पर रोकथाम की बजाय प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने की ओर देना होगा। सरकार ने इन सारे मुद्दों पर विचार करने और हमारी स्थितियों के अनुरूप एक आधुनिक प्रतिस्पर्द्धा कानून का प्रस्ताव करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है।
- 24. व्यापार और उद्योग सम्बन्धी प्रधानमंत्री की परामर्शदात्री परिषद ने ज्ञान पर आधारित उद्योगों के बारे में महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। औषधि उद्योग महत्वपूर्ण ज्ञान पर आधारित उद्योगों में से एक है जहां हमें अपेक्षतया अधिक फायदा हासिल होता है। हमें हमारे दवा उद्योग के अनुसंघान और विकासात्मक क्षमताओं को सुदृढ़ करना होगा। सरकार ने वर्तमान औषधि नीति की पुनरीक्षा के लिए दो उच्च स्तरीय समितियां गठित करने का निर्णय किया है जिससे मूल्य नियन्त्रणों की सख्ती में, जहां वह उत्पादन के प्रतिकूल बन चुकी हैं, कमी लाई जा सके और भारतीय औषधि कम्पनियों के लिए स्वदेशी अनुसंघान व विकास का काम हाथ में लेने हेतु आवश्यक सहायता का पता लगाया जा सके। मेरे सहयोगी, रसायन व उर्वरक मंत्री इस प्रयास के बारे में अलग से घोषणा करेंगे। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्रक में दिदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने स्वतः माध्यम के तहत 74 प्रतिशत इ क्वेटी की अनुमित देने का निर्णय किया है।

- 25. हमने अपना ध्यान जहां एक ओर नये उभर कर आने वाले उद्योगों की ओर दिया है, वहीं हमने वस्त्रोद्योग जिसमें 380 लाख कामगार कार्यरत हैं और जो विनिर्माण मूल्यवर्धन का लगभग 20 प्रतिशत का योगदान करते हैं, जैसे स्थापित उद्योगों की उपेक्षा भी नहीं की है। सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्ययन निधि स्कीम को मंजूरी दी है और यह अप्रैल, 1999 से लागू हो जाएगी। इसमें अगले पांच वर्षों के लिए वस्त्रोद्योग इकाइयों द्वारा वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से लिए गए ऋणों पर 5 प्रतिशत के पर्याप्त ब्याज प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें बुनकरी, बुनाई, प्रसंस्करण और फिनिशिंग इकाइयां, वस्त्र उत्पादन, रुई ओटना और प्रसंस्करण और जूट उद्योग शामिल होंगे। इस स्कीम का दायरा बढ़ाकर कताई उद्योग को भी शामिल किया जा रहा है।
- 26. सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे में हमारी सरकार ने हथकरघा बुनकरों के लिए सेवाएं, तकनीकी और विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए हथकरघा क्षेत्रक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पहले ही जाहिर कर दी है। विपणन के क्षेत्र में, मेरा एक नई समेकित हथकरघा संवर्धन स्कीम, 'दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना' शुरु करने का प्रस्ताव है जिससे बुनकरों के लिए करण सुविधायं, नई डिजाइन सामग्री और हथकरघा वस्त्रों के विपणन हेतु नये साधनों की जाप्ति को प्रोत्साहन मिलेगा।
- 27. सरकार बिजली, दूरसंचार, सड़क और पत्तनों जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रकों में महत्वपूर्ण कानूनी एवं दूसरी सुधारात्मक पहलें कर चुकी है।
- 28. सेतु समुद्रन शिप केनाल परियोजना हमारे देश के पूर्वी और पश्चिमी पत्तनों के बीच छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करेगी। दीर्घकाल से प्रतीक्षित इस परियोजना की तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता की जांच करने के लिए मैं 1999-2000 के दौरान निधियां प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

लघ् उद्योग

- 29. गत वर्ष मैंन लघु उद्योग क्षेत्रक को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की थी। इस क्षेत्रक को ऋण प्रदान करना हमारे बैंकिंग क्षेत्रक के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। लघु उद्योग के लिए ऋण वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:
 - ' लघु ऋणकर्त्ताओं को एकल खिड़की के माध्यम से सावधिक ऋण और कार्यशील पूंजी प्रदान करके उनकी प्रक्रियात्मक किटनाइयों को दूर करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बेंक और वाणिज्यिक बैंकों की संयुक्त स्कीम तैयार की गयी है। इस समय संयुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए है। मेरा इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव हैं।
 - ' लघु उद्योग इकाइयों की कार्यशील पूंजी सीमाओं की संगणना के सरलीकरण के लिए मेंने पिछले वर्ष यह घोषणा की थी कि 4 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली लघु उद्योग इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी सीमा वार्षिक कारोबार के 20 प्रतिशत पर नियत की जाएगी। मेरा इस सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।
 - भारतीय रिजर्व बँक द्वारा नियुक्त एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को तदर्थ ऋण सीमाओं को प्रदान करने में शाखा प्रवन्धकों को अधिक अधिकार प्रत्यायोजित करने, आवेदन प्रपन्नों को सरल बनाने, ऋण जरूरत के आकलन के लिए उनके खंय के मानदण्ड तय करने तथा और अधिक लघु उद्योग शाखाएं खोलने की सलाह दी थी। इन उपायों से लघु उद्योग इकाइयों को बैंक ऋणों की प्राप्ति में आसानी होनी चाहिए।

- लघु क्षेत्रक तक बैंकों की पहुंच बढ़ाने के लिए, बैंकों द्वारा गैर बैंकिंग वित्त कम्पनियों अथवा अन्य वित्तीय मध्यवर्ती कारोबारियों को आगे लघु क्षेत्रक को ऋण प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए ऋण प्रदान करने को बेंक ऋण प्रदायगी के प्राथमिक क्षेत्रक की परिभाषा में शामिल किया जा रहा है।
- वैंकों को पर्याप्त जमानत उपलब्ध कराने में असमर्थता और कम वसूली को प्रायः लघु उद्योग इकाइयों के लिए निवेश ऋण की प्राप्ति में प्रमुख बाधा माना जाता है। यह समस्या निर्यातोन्मुखी और लघु उद्योग इकाइयों के मामले में अधिक प्रबल है। इस समस्या के निराकरण के लिए एक नई ऋण बीमा स्कीम शुरू की जाएगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- 30. हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का जयगान करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने "जय विज्ञान" का एकदम सटीक नारा दिया था। समय आ चुका है कि हम अपने वैज्ञानिकों और आधारभूत स्तर के खोजकर्ताओं की सृजनात्मक क्षमता को उजागर करें। केवल तभी हम भारत को सच्चे अर्थों में आत्म निर्भर और सुदृढ़ प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अग्रणी बना सकते है। मैं समूचे देश में नवीन खोजकर्ताओं की मदद के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठान बनाने का प्रस्ताव करता हूं। 20 करोड़ रुपए की आरम्भिक धनराशि से शुरु की गई इस निधि से खोजों का एक राष्ट्रीय रिजस्टर तैयार किया जाएगा, बौद्धिक सम्पदा संरक्षण की व्यवस्था होगी, नवीन खोजों को सक्षम कार्यों में बदलने और इन खोजों का देशभर में प्रसार करने के लिए इनक्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी।
- 31. हमारी अनुसंधान संस्थाओं के पास ऐसी नई वैक्सीनें विकसित करने की क्षमता है जो चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रणालियों के क्षेत्र में क्रान्तिकारी हो सकती हैं। इस प्रयास की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए हमारा वैक्सीनों के सम्बन्ध में एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- 32. हमारा देश ऐसे विविध और बहूमूल्य आनुवंशिक संसाधनों से सम्पन्न है जिनका उचित रूप से संरक्षण व प्रबन्धन किए जाने की आवश्यकता है। विश्व में जैव विविधता के 18 जीवन्त क्षेत्रों में से दो भारत में क्रमशः पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाटों में आते हैं। इस महत्यपूर्ण क्षेत्र में नीतियों, अनुसधान प्रलेखीकरण और देश के अधिकारों के कानूनी संरक्षण के समन्वय के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जैव संसाधन बोर्ड (एन.बी.बी.) की स्थापना की जाएगी।

बैंकिंग

- 33. गत वर्ष मैंने बैंकिंग क्षेत्रक में सुधारों के बारे में नरिसम्हन समिति की रिपोर्ट के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की थी। बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे की अनुवर्ती कार्रवाई की है। मेरा सुधार प्रक्रिया को और आगे ले जाने का प्रस्ताव है:
 - हमारे सरकारी क्षेत्रक के बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों का उच्च स्तर निरन्तर चिन्ता का विषय बना हुआ है। त्वरित न्यायनिर्णयन और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली के लिए गठित ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डी.आर.टी.) के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आने लगे हैं। सरकार ने 5 और डी.आर.टी. और 4 ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का निर्णय किया है। मेरा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम में इसके उपबन्धों को सुदृढ़ करने हेतु इसमें कतिपय संशोधन करने के लिए संसद के चालू सत्र में एक विधेयक पेश करने का भी प्रस्ताव है।
 - कमजोर बैंकों की पुनर्सरचना और उनकी गैर निष्पादनकारी पिरसम्पत्तियों की समस्या

से निपटने के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करने के लिए हमने हाल ही में एक कार्यकारी दल की स्थापना की है।

- अतिदेय ऋणों के बहुत पुराने मामलों का समय पर समझौता निपटान करने में बैंकों की असमर्थता बैंकों की निधियों की अवरुद्धता और वसूली वादों में लम्बे समय तक चलने वाले मुकदमेबाजी का कारण बनती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समझौता सलाहकार समितियां गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि इस प्रकार के बहुत पुराने मामले, विशेषकर लघु क्षेत्रक से सम्बन्धित मामलों का समय पर और शीघ्रतापूर्वक निपटान हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक इस बारे में बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा।
- ' हमारे बैंकों को सन्देहास्पद और गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों के प्रति व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्डों का अनुपालन करने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में इन मानदण्डों को सुदृढ़ किया गया है। विवेकपूर्ण मानदण्डों के अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों तक आने में बैंकों की मदद के लिए किए गए प्रावधानों की कर कटौती में कतिपय परिवर्तनों की मैं धोषणा करूंगा।

वैदेशिक क्षेत्रक

34. अपनी विदेशी भुगतान की स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें अपने निर्यातों में फिर से नई जान फूंकने और विदेशी निवेश के रूप में और अधिक गैरं ऋण प्राप्तियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगेः

- लदान-पूर्व और लदान-पश्च ऋण को अन्तर्राष्ट्रीय रुप से प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर उपलब्ध कराने और प्रक्रियाओं का बहुत अधिक सरलीकरण करने के लिए विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण की मीजूदा स्कीम में आमूल-चूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में ब्यौरों की अलग से घोषणा करेगा।
- फिये गये अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि हमारे निर्यातकों को विदेशी व्यापार लाइसेंस प्रणाली, कर प्रणालियां और बैकिंग प्रणाली से सम्बन्धित उच्चतर लेनदेन लागतों की बाधा का सामना करना पड़ता है। मैं इस समस्या पर गहराई से विचार करने और ऐसे लेनदेन की लागतों में कमी लाने के लिए तीन महीने के भीतर ठोस सिफारिशें करने के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना कर रहा हूँ।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राप्ति को बाधा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रकों को शामिल करते हुए स्वतः अनुमोदन की सूची को विस्तृत करने का निर्णय लिया है। विस्तारित सूची की घोषणा पृथक रूप से उद्योग मंत्री द्वारा की जाएगी। जहां कहीं विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) की स्वीकृति अपेक्षित होगी, वहां एफ.आई.पी.बी. अपना निर्णय 30 दिन के भीतर देगा।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) स्वीकृतियों के मंदगति से कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस बात का सुनिश्चयन करने के लिए ऐसी स्वीकृतियों को शीघ्रता से वास्तविक निवेश प्राप्तियों तथा परियोजनाओं में परिणत किया जाए, सरकार ने उद्योग मंत्रालय के अधीन एक विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) गठित करने का निश्चय किया है जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं।
- देश में परिवारों तथा कई धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाओं द्वारा सोने की काफी मात्रा अपने पास रखी गयी है। यह अनुत्पादक परिसम्पत्तियां हैं जिनसे धारकों को कोई आय

प्राप्त नेहीं होती और वह अक्सर इन परिसम्पत्तियों की सुरक्षा पर खर्च करते हैं। यह एक ऐसी विसंगति है कि देश को प्रतिवर्ष सोना रखने की नयी मांग को पूरा करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए की राशि विदेशी मुद्रा में व्यय करनी पड़ती है। इस अनुत्पादक सोने को जुटाने के लिए, मैं एक नई स्वर्ण जमा योजना का प्रस्ताव करता हूँ। चुनिंदा बैंको को सोना जमा करने और सब्याज प्रमाण पत्रों अथवा बाण्डों के जारी करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इनके परिपक्व हो जाने पर इन प्रमाण पत्रों अथवा बाण्डों के बदले सोना पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे जमाकर्त्ताओं को अपने पास पड़े सोने के भण्डारण, सचालन और सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी और उन्हें आय का एक नियमित स्रोत भी उपलब्ध होगा। देश के सम्बन्ध में इस बेकार पड़े सोने को काम में लेकर हमारी आयातित सोने पर निर्भरता कम होगी। इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए मैं स्वर्ण जमा बांडों/प्रमाण पत्रों से प्राप्त ब्याज को आयकर से और स्वर्ण जमा योजना में जमा की गयी परिसम्पत्तियों के मूल्य को धन कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, इन स्वर्ण बांडों/प्रमाणपत्रों से व्यापार अथवा मोचन के जरिए प्राप्त पूंजीगत लाभों को पूंजीगत लाभ कर से छूट प्रदान की जाएगी। मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि इस योजना के तहत शामिल किए गए स्वर्ण की आवाजाही को चुंगी, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क और इसी प्रकार की अन्य लेवी से छूट प्रदान करने के बारे में विचार करें। मैं यह भी उल्लेख करना चाहंगा कि इस योजना से सभी प्रकार के सोने में छूट नहीं मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

- मैंने अपने पिछले बजट में, हमारे देश के विकास में अनिवासी भारतीयों की भागीदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया था। उनकी प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर अब मैं कुछ और प्रोत्साहनों का प्रस्ताव करता हूँ:
 - हम अनिवासी भारतीयों/समुद्रपारीय निगमित निकायों द्वारा किए जाने वाले 100 प्रतिश्वत तक के निवेश के सम्बन्ध में सभी मदों के लिए स्वतः स्वीकृति की सुविधा प्रदान करेंगे परन्तु इसमें वे मदें शामिल नहीं होंगीं जिन पर अधिसूचित एफ डी आई इक्विटी कैप्स लगता है अथवा जिन्हें औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अधिसूचित अनिवार्य लाइसेंसिंग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का संरक्षण प्राप्त है अथवा जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।
 - हमारे प्रमुख स्टॉक एक्सचेन्जों में प्रतिभूतियों के लिए स्क्रीन आधारित स्वतः कारोबार की व्यवस्था है। अब स्टॉक एक्सचेन्जों के लिए तकनीकी तौर पर विदेशों में कारोबार टर्मिनलों का खोलना सम्भव हो गया है जिससे हमारे पूंजी बाजारों में अनिवासी भारतीयों की भागीदारी सुगम होगी। मैंने भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) से इस उद्देश्य हेतु इसके तौर तरीकों को तैयार करने के लिए कहा है।
 - भारतीय म्युचुअल फंडों में अनिवासी भारतीयों के निवेश के सम्बन्ध में मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्रदान करने सम्बन्धी व्यवस्था को कार्योत्तर सूचना प्रणाली के रूप में सरल बनाया जाएगा।

पूंजी बाजार

35. हमारे आधारभूत सुविधा क्षेत्रक के लिए अति आवश्यक निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक सक्षम पूंजी बाजार का होना अनिवार्य है। आधारभूत परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक निधियों की आवश्यकता होती है और जिसके लिए एक सुदृढ़ और सुचारु रूप से कार्य करने वाले

ऋण बाजार की आवश्यकता होती है। ऋण बाजार को आधुनिक बनाने तथा इस क्षेत्र में कागजी कार्रवाई रहित लेनदेन आरंभ करने के उद्देश्य से भी सरकार जमा प्रणाली के अन्तर्गत ऋण दस्तावेजों के अन्तर्शण पर स्टाम्प शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव करती है।

- 36. हाल ही में, भारतीय कम्पनियों के अच्छे प्रशासन के महत्व पर पर्याप्त चर्चा हुई है। यह बराबर महसूस किया जा रहा है कि निवेशकों को पूंजी बाजार में पुनः आकर्षित करने के लिए कम्पनियों को निगमित प्रतिष्ठानों के प्रशासन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य कार्यप्रणालियों का पालन करके अपने को सुव्यवस्थित रखना पड़ेगा। निवेशक के विश्वास को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए में कंपनी प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु एक राष्ट्रीय पुरस्कार चालू करने का प्रस्ताव करता हूं।
- 37. यू.टी.आई. द्वारा नियुक्त दीपक पारिख समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं जिनमें यू.एस.-64 स्कीम की पुनर्संरचना और कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सिफारिशें भी शामिल हैं। हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। मैं शीघ्र ही कर प्रोत्साहनों का उल्लेख करुंगा। पुनर्संरचना से संबंधित ब्यौरों की घोषणा अलग से प्रेस रिलीज में की जा रही है। इससे पूंजी बाजार में अनिश्चितता के बादल छंट जाने चाहिए और विश्वास की बहाली होनी चाहिए।
- 38. मेरे कर-प्रस्तावों से म्युचुअल फंड भी काफी सुदृढ़ होंगे और इसके द्वारा छोटे फुटकर निवेशक पूंजी बाजार में वापस लीटेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे बेईमान प्रमोटरों जो निवेशकों से धन जुटाकर उसका गलत उपयोग करते हैं, के विरुद्ध कटोर कार्रवाई करने कैं लिए 'सेबी' तथा कम्पनी कार्य विभाग के बीच एक संयुक्त तंत्र की स्थापना की जाए।

व्यय प्रबन्ध

- 39. सरकार द्वारा किए जा रहे गैर विकासात्मक व्यय की उच्च वृद्धि दर चिन्ता का एक बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण कारण है। मैं निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव करता हूं:
 - इस समस्या का सर्वाधिक कारगर तथा चिरस्थायी समाधान सरकार के आकार को छोटा बनाने की प्रक्रिया आरंभ करना है। केन्द्र सरकार के विमागों में आमेलन और उन्हें युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से हम चार सिंख स्तरीय पदों को समाप्त कर इस दिशा में तत्काल शुरुआत कर रहे हैं। इसे 1 अप्रैल, 1999 से लागू किया जाएगा।
 - सरकार की भूमिका तथा उसके प्रशासनिक ढांचे को कम करने की दिशा में इस प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे ले जाने के लिए हम एक प्रतिष्ठित तथा अनुभवी व्यक्ति की अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग का गठन करेंगे।
 - ' मैं अगले बजट को तैयार करने में पुनर्मूल्यांकन (जीरो बेस) आधारित बजट प्रणाली बनाने का प्रस्ताव करता हूं।
 - पारदर्शिता को प्रोत्साहन देने तथा सरकार की आकस्मिक देयताओं में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए, सरकार ने 50 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि से एक गारंटी शोधन निधि की स्थापना करने का निर्णय लिया है। ऐसी ही निधियां स्थापित करने के लिए मैं सभी राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करता हूं।

सरकारी क्षेत्र के सुधार/विनिवेश/निजीकरण

40. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रति सरकार की कार्य-नीति में महत्वपूर्ण यूनिटों को सुदृढ़ करना, क्रमिक विनिवेश अथवा अनुकूल बिक्री के जरिए गैर-महत्वपूर्ण यूनिटों का निजीकरण और कमजोर यूनिटों के लिए व्यवहार्य पुनर्वास की कार्यनीति बनाना जैसे मिश्रित उपाय शामिल होंगे।

- 41. सरकार का विनिवेश संबंधी कार्यक्रम मूल रूप से विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर तैयार किया जाता है। आयोग ने अब तक 8 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं जिनमें 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संवंध में सिफारिशें दी गयी हैं। ये सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के और उद्यमों को विनिवेश आयोग के पास उसकी महत्वपूर्ण सलाह प्राप्त करने के लिए भेजेगी। मैं वर्ष 1999-2000 में विनिवेश कार्यक्रम के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव करता हूं। इससे सरकार को सामाजिक तथा आधारभूत क्षेत्रकों की आवश्यकताओं के लिए निधि प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ इन उद्यमों की उत्पादकता तथा लाभकारिता में सुधार होगा और घरेलू पूंजी वाजारों का आगे विकास भी होगा।
- 42. सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के अंतर्गत जनशक्ति को सुसंगत बनाने हेतु केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बजटीय सहायता प्रदान करती रही है। परन्तु, ऐसी सहायता सामान्यतः घाटे में चल रहे उद्यमों तक सीमित है। ऐसे और भी उद्यम हैं जो मामूली मुनाफा अर्जित कर रहे हैं और जिन्हें चल सकने योग्य बनाए रखने के लिए उनकी जनशक्ति को घटाने की आवश्यकता है लेकिन ऐसे युक्तिसंगत कार्यों के वित्तपोषण हेतु इन उद्यमों के पास संसाधन नहीं हैं। सरकार ऐसे उद्यमों को बैंकों से सरकारी गारंटियों पर तथा ब्याज सब्सिडी से धन जुटाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- 43. स्वैच्छिक सवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के कारण बजट पर पड़ने वाले बोझ को कम करने की दृष्टि से, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने वाले कामगारों के लिए बांड जारी करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। सरकार ऐसे बाण्डों की पुनःअदायगी की गारंटी देगी और साथ ही ब्याज भुगतानों की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया जाएगा कि वह ऐसे कामगारों, जिन्हें सहायता की जरुरत है, को ऋण की स्वीकृति के संबंध में ऐसे बाण्ड सहवर्ती रूप में स्वीकार करने हेतु बैंकों, को आवश्यक अनुदेश जारी करे।
- 44. नीति तैयार करने तथा योजना बनाने के संबंध में समय पर विश्वसनीय सांख्यिकी की आवश्यकता के महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह विश्वास योग्य है कि आर्थिक नियंत्रण प्रणाली को उत्तरोत्तर समाप्त करने से आंकड़े प्राप्त होने की गुणवत्ता में गिरावट आयी है। सरकार ने मौजूदा सांख्यिकीय प्रणाली की किमयों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है तािक प्रणाली को व्यवस्थित तरीके से पुनः सुदृढ़ करने के लिए उपायों की सिफारिश की जा सके।
- 45. आज हम द्वितीय सहस्त्राब्दि के अंतिम छोर पर खड़े हैं। इसलिए हमें आगामी शताब्दी तथा सहस्त्राब्दि से उत्पन्न अवसरों तथा चुनौतियों के लिए तैयार रहना है। दूसरी पीढ़ी के सुधारों के संबंध में गम्भीरता से चर्चा करने तथा उन पर निर्णय लेने का यह समय है तािक उन सुधारों से हम भारत को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बना सकें और नवोदित विश्व व्यवस्था के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट सत्र की समाप्ति से पहले मेरा विचार संसद के समक्ष एक चर्चा पत्र लाने का है। मेरा उद्देश्य बुनियादी मुद्दों पर एक सर्वसम्मति बनाने में सहायता करना है तािक हम आय में बढ़ोतरी और अपनी अर्थव्यवस्था में रोजगार का अपेक्षाकृत उच्च और स्थायी स्तर पर बनाए रखने के लिए और अधिक निर्णायक रूप से कार्य कर सकें।

संशोधित अनुमान, 1998-99

46. आयोजना-भिन्न व्यय में 17,616 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई है। आयोजना के अंतर्गत 3631 करोड़ रुपए की कमी आई है। सरकारी विभागों का आयोजना-भिन्न व्यय केवल 2539 करोड़ रुपए बढ़ा है। अन्य वृद्धियां निवल अल्प बचत संग्रहणों, 9588 करोड़ रुपए के एवज

में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऋणों, पेंशन, 2711 करोड़ रुपए, ब्याज भुगतान, 2248 करोड़ रुपए और डाक घाटा, 530 करोड़ रुपए के कारण हैं।

- 47. केन्द्र का निवल कर राजस्व, बजट में 116857 करोड़ रुपए की तुलना में 109537 करोड़ रुपए अनुमानित है जो 7320 करोड़ रुपए की कमी प्रदर्शित करता है। यह कमी मुख्यतः आयातों की कम मात्रा और कम इकाई मूल्य दोनों के कारण कम सीमाशुल्क राजस्व तथा कम औद्योगिक वृद्धि के परिणामस्वरूप कम उत्पाद शुल्क राजस्व के कारण हुई। विनिवेश प्राप्तियां बजट के अनुसार 5000 करोड़ रुपए की तुलना में 9000 करोड़ रुपए होना अनुमानित हैं।
- 48. इस प्रकार राजकोषीय घाटा तुलनीय सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों के आधार पर 5.6 प्रतिशत के बजट लक्ष्य की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 6.5 प्रतिशत तक बढ़ना संभावित है। तथापि, अगर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लघु बचत के लिए ऋणों के कारण बजट में वृद्धि को छोड़ दिया जाए तो समायोजित राजकोषीय घाटा 5.9 प्रतिशत होगा।

बजट अनुमान, 1999-2000

49. वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमान में 284003 करोड़ रुपए का कुल व्यय अनुमानित है, जिसमें से 77000 करोड़ रुपए आयोजना और 207003 करोड़ रुपए आयोजना-भिन्न के लिए हैं।

आयोजना य्यय

- 50. केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बजटीय सहायता 77000 करोड़ रुपए रखी गई है, जो संशोधित अनुमान, 1998-99 की तुलना में 8629 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाती है। प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसरण में वर्ष 1999-2000 की आयोजना शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, सामाजिक कल्याण, आवास और जलापूर्ति जैसे बुनियादी मानव विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करती है। इस प्रकार, केन्द्रीय आयोजना, 1999-2000 के लिए 44,000 करोड़ रुपए की कुल सकल बजटीय सहायता में से 31,035 करोड़ रुपए प्रधानमन्त्री की विशेष कार्य योजना के अधीन आने वाले 18 मंत्रालयों/विभागों को प्रदान किए गए हैं। कुल 103521 करोड़ रुपए का केन्द्रीय आयोजना परिव्यय पिछले वर्ष के 88,482 करोड़ रुपए के स्तर से 15039 करोड़ रुपए अधिक होगा। केन्द्रीय आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता वर्ष 1998-99 के संशोधित अनुमान में 38,263 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 44,000 करोड़ रुपए की जा रही है।
- 51. संशोधित अनुमान 1998-99 की तुलना में आयोजना कार्यक्रमों के लिए बजटीय सहायता कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में काफी बढ़ी है। उदाहरण के लिए, यह वृद्धियां कृषि एवं संबंधित क्रियाकलापों में 34.5 प्रतिशत और सामाजिक सेवाओं में 21.9 प्रतिशत है।
- 52. वर्ष 1999-2000 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय आयोजना सहायता, वर्ष 1998-99 के संशोधित अनुमान में 30108 करोड़ रुपए की तुलना में 33000 करोड़ रुपए रखी गई है। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं और झुग्गी झोपड़ी विकास स्कीमों के लिए सहायता राशि 3684 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4043 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।
- 53. पिछले वर्ष मैंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक कालातीत न होने वाले पूल की घोषणा की थी। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हमने विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के बजट की बचतों में से पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 98 करोड़ रुपए पहले ही रिलीज कर दिए हैं।

आयोजना-भिन्न व्यय

54. वर्ष 1999-2000 में आयोजना-भिन्न व्यय वर्ष 1998-99 के संशोधित अनुमान में 213541 करोड़ रुपए की तुलना में 207003 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। यह वास्तव में 232003 करोड़ रुपए हुआ होता परन्तु दिनांक 1.4.1999 से निवल लघु बचत संग्रहणों के एवज में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण देने की लेखा प्रणाली में परिवर्तन किए जाने से ऐसा नहीं हुआ। यह परिवर्तन, जो लघु बचत स्कीमों की स्पष्टता और व्यवहार्यता के हित में है, केन्द्रीय राजकोषीय घाटे से लघु बचतों को असंबद्ध करने पर दिसम्बर, 1998 में अन्तर्राज्यीय परिषद में दिए गए सुझाव को मानते हुए किया गया है। श्री आर.वी. गुप्ता की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने इस मुद्दे पर विचार किया। समिति की सिफारिशों के आधार पर और भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की सहमति से लेन-देन अब एक नई सृजित राष्ट्रीय लघु बचत निधि के अधीन लोक खाते में होगा, जो इन कार्यों की राजकोषीय बैंकिंग प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा। समिति की रिपोर्ट की एक प्रति माननीय सदस्यों के सूचनार्थ संसद के पुस्तकालय में रखी जा रही है।

- 55. आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि की मुख्य मदें ब्याज संदाय-10752 करोड़ रुपए, रक्षा व्यय-4494 करोड़ रुपए और राज्यों को अनुदान-3621 करोड़ रुपए हैं। रुग्ण और रुग्णता से उबर रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को मुख्यतः वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आयोजना-भिन्न ऋण के लिए 1735 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
- 56. वर्ष 1998-99 के संशोधित अनुमान में 41200 करोड़ रुपए की तुलना में रक्षा व्यय के लिए 45694 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान आवश्यकता-आधारित बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी।

राजस्य प्राप्तियां

57. अपने कर प्रस्तावों का विवरण देने से पूर्व मैं अगर मौजूदा करों की दरें और टैरिफ जारी रहीं तो वर्ष 1999-2000 में राजकोषीय घाटे की स्थिति का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। सकल कर राजस्व तब 167526 करोड़ रुपए होगा और केन्द्र का निवल कर राजस्व 122730 करोड़ रुपए होगा। कर-भिन्न राजस्व के संशोधित अनुमान, 1998-99 में 48128 करोड़ रुपए से इस वर्ष बढ़कर 50475 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। केन्द्र के लिए कर-भिन्न प्राप्तियों सहित निवल राजस्व प्राप्तियों संशोधित अनुमान, 1998-99 में 157664 करोड़ रुपए से वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 173205 करोड़ रुपए हो जाएंगी। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के विनिवेश से 10000 करोड़ रुपए की प्राप्ति को हिसाब में लेते हुए 89713 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा होगा। यह अस्वीकार्य रूप से अत्यधिक है। अब मैं घाटा कम करने के लिए अपने प्रस्तावों की चर्चा करुंगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Budget Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 1999

No. F.15(1)-B(D)/99.—The following is published for general information:—

Budget 1999-2000 Speech of

Shri Yashwant Sinha

Minister of Finance

27th February, 1999

PART A

Sir,

I rise to present the budget for the year 1999-2000.

Introduction

2. For the first time after Independence with the enthusiastic support of all political parties in Parliament, it has been possible for me to discard the long standing tradition of British Raj of presenting the budget at 5 PM. A new beginning is being made today as I present the last Budget of 1900's. I assure you this is not the only new feature. There are many more in this budget.

The Economic Context

- 3. The decade of the nineties has witnessed extraordinary changes. It began with the collapse of the centrally planned economies; it is ending with market economies facing a serious crisis.
- 4. The year 1998 particularly has been a year of unprecedented global turmoil. The East Asian financial crisis took a heavy toll of important economies in the region and spread to other countries. Japan continued in recession and in August 1998 severe crisis afflicted Russia. By January 1999, the contagion had spread to Brazil triggering massive capital flight and a steep depreciation of the currency. World output growth dropped below 2%, the growth of world trade decelerated sharply, commodity prices fell steeply, currencies were savaged and capital flows to developing countries declined sharply.
 - 5. In India, we had to contend with the additional challenge

of economic sanctions imposed on us after the Pokhran nuclear tests. While we have not remained unaffected by these developments, we have reasons to be satisfied at the way we have withstood the impact of these challenges. Despite the hostile economic environment, our GDP growth in 1998-99 has accelerated to 5.8% compared to 5% last year. Our farmers have led the way with 5.3% growth in agriculture and allied sectors. Since the beginning of 1998-99, we have added \$2 billion to our foreign currency reserves as of February 23, 1999 and we have successfully curbed undue volatility in the forex market. The current account deficit in the balance of payments is estimated at a modest 1.4% of GDP compared to 1.6% in 1997-98. Although inflation had risen sharply during the year, we have succeeded in bringing it down to below 5% now. All this is described in detail in the Economic Survey presented to Parliament a few days ago.

- 6. However, there is no room for complacency. The challenges before us, both international and domestic, remain grave. The fiscal and revenue deficits of both Centre and States are still too high and are undermining our ability to bring down interest rates, stimulate investment and growth, curb inflationary potential, generate resources for priority, non-interest expenditure needs and raise exports.
- 7. Above all, despite our continuing concern year after year, we have made only a limited impact on the problems of poverty and unemployment. The various schemes of the Government in this area lack focus and convergence. The delivery systems need to be cost effective and community based. The fruits of economic development should largely reach the poor and the vulnerable specially the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who, in turn, need to be empowered fully. Without this, I am afraid, our planning will be devoid of any direction.
 - 8. The broad strategy of this Budget therefore is six-fold:
 - * Begin a medium-term process of revenue and fiscal deficit reduction, along the lines indicated in the Ninth Plan, which will free more resources for productive investment and growth and contain inflation.
 - * Undertake a major reform of indirect taxes to promote productivity and employment.
 - * Deepen and widen economic reforms in all major sectors and accelerate internal liberalization to release the

productive energies and creativity of our farmers, manufacturers, traders and service providers.

- * Safeguard the economy from external shocks, revive exports and stimulate the domestic engines for growth revival.
- * Strengthen the knowledge-based industries and thus prepare ourselves for the challenges of the new millennium.

Last but not the least

* Revitalise and redirect public programmes for human development, encompassing food security, health care, education, employment and shelter. Their focus should be on empowering the poor and the weaker sections, especially those belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Agriculture and Rural Development

- 9. This year's growth performance has once again underlined the critical importance of agriculture in our economy. I propose a multi pronged programme to further strengthen our rural economy.
- 10. On water, which is the lifeblood of agriculture, I propose the following initiatives:
 - It is important to unify the multiplicity of watershed development programmes within the framework of a single national initiative a National Movement of Watershed Development that fosters implementation ability at the local level and creates community infrastructure for micro watershed projects through active involvement of Gram Panchayats, Local Self Help Groups and NGOs. For this, a Watershed Development Fund will be established with NABARD to cover 100 priority districts within 3 years. The Central Government will provide necessary matching assistance to NABARD. This will create income generating opportunities for the landless and the poor; especially those belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.
 - * The Accelerated Irrigation Benefit Programme aims to expedite the completion of ongoing irrigation projects by providing matching assistance to States. However, the water rates in most States do not even cover full

Operations and Maintenance costs. To encourage better management and maintenance of costly irrigation assets, the Centre will provide larger financial assistance to States that rationalise their water rates to cover at least O&M costs.

- In order to promote farmer participation in water management, the Centre will provide a one time management subsidy and recurring assistance over an initial period of 3 years to all registered Water Users Associations, linked to incremental water rate collection. This will supplement the States' own contribution.
- 11. Water and credit must flow together for maximum impact. Last year, I had announced a number of initiatives for improving the flow of credit from the banking sector to agriculture. I am happy to report to this House that institutional credit flow to agriculture has shown a 20% increase in the current year, taking the level to about Rs.38,000 crore as compared to Rs.31,698 crore in the previous year. I propose to take the following further measures for improving flow of agricultural and rural credit:
 - * The Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) has emerged as an important scheme for financing rural infrastructure projects of the State Governments. Last year, I had announced an allocation of Rs.3,000 crore from the banking sector under RIDF IV. I propose to continue the scheme. The corpus of RIDF V will be raised to Rs.3,500 crore. The repayment period is also being extended from five to seven years. The scope of RIDF will also be widened to allow lending to Gram Panchayats, Self-Help Groups and other eligible organisations for implementing village level infrastructure projects.
 - In line with my announcement last year, the Kisan Credit Card Scheme has been launched by all public sector banks. These Cards provide timely credit to farmers in a flexible and cost effective manner. So far, six lakh Kisan Credit Cards have been issued. I am asking public sector banks to extend the coverage so that twenty lakh farmers can benefit from this scheme in the coming year.
 - * The reform measures initiated to strengthen and restructure the Regional Rural Banks will continue. A provision of Rs.168 crore is being made for recapitalisation of RRBs.

- Micro enterprises have great potential for generating productive employment, especially in rural areas. NABARD and SIDBI have launched schemes for promotion of Self Help Groups and NGOs as a channel for flow of funds to micro enterprises. Following last budget's initiative, NABARD is likely to cover about 15,000 Self Help Groups in 1998-99, as against the target of 10,000. I am asking NABARD and SIDBI to redouble their efforts in this direction and ensure coverage of at least 50,000 Self Help Groups during the course of the next year.
- * To augment the flow of credit for food and agro processing industries, lending by banks to this sector will be treated as priority sector lending.
- 12. Today, we have a very weak post-harvest storage and marketing infrastructure. This causes tremendous national loss. To overcome this problem, I propose to introduce a new credit-linked capital subsidy scheme for construction of cold storages and godowns. This scheme, which will be implemented by the Ministry of Agriculture with the help of NABARD, will help create additional cold storage capacity of 12 lakh tonnes and will rehabilitate and modernise 8 lakh tonnes of existing units over the next few years. We also propose to create 4.5 lakh tonnes of onion storage capacity. This House, especially the main opposition party, can readily appreciate our special concern for onions.
- 13. Fragmentation of agricultural land holdings undermines productive use of land. Some States have lagged behind in attending to this important task of land reforms. To accelerate reforms in this direction, the Central Government will provide special financial assistance to States, which undertake this task.
- 14. One of the problems with effective distribution and use of fertilizer is the mismatch between its demand and availability at the on-set of the sowing operations. In order to tackle this problem, I propose to experiment with an incentive discount to farmers for lifting fertilizer from the cooperative societies during the lean months of April and May.
- 15. The on-going schemes for the development of degraded and wastelands will be reoriented to permit local Self Help Groups and the landless poor, specially Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, to develop and utilise such lands in each village. The whole programme will be based on participatory management with the Gram Panchayat having a

pivotal role. During 1999-2000, we will earmark a total amount of Rs.50 crore to take up this scheme on an experimental basis in those States that are prepared to put in a matching contribution.

National Programme for Rural Industrialisation (NPRI)

Rural Industrialisation is important for creating employment opportunities, raising rural incomes and strengthening agriculture-industry linkages. Thus far, it has been pursued by a multiplicity of government agencies. However, the impact of these programmes at the grass roots level has remained modest. We must integrate the efforts of the various government agencies and ensure active community participation. Accordingly, I propose a National Programme for Rural Industrialisation (NPRI) with the mission to set up 100 rural clusters every year to give a boost to rural industrialisation. This is being done for the benefit of rural artisans and unemployed youth. In the long run, it will reduce rural urban disparities. The Small Industry Development Organisation will coordinate this programme. The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) will play an important role in this. The marketing infrastructure available with KVIC would be put to optimum use in this effort. It will go a long way in the marketing of rural industrial products if KVIC could develop its own brand name for the purpose. The proposed rural clusters will be spread throughout the country, with a reasonable balance between high potential and backward rural areas.

National Human Development Initiative (NHDI)

17. Even a half-century after Independence, the levels of human development in India lag behind most other countries. The essence of human development should be to empower vulnerable groups in society to take advantage of the process of development. Empowerment, in my view, entails access to five basic requirements, namely, Food, Health Care, Education, Employment and Shelter. It is our resolve to make them available to the entire population of this country within a decade. With this initiative for people-centred development, we will be implementing the Prime Minister's mandate for 'reforming the reforms'.

Food: The Targeted Public Distribution System has been designed to provide food security, especially to those below the poverty line, on the basis of susbidised foodgrain prices. With greater involvement of Gram Panchayats in its supervision and implementation, the Targeted Public Distribution System will be suitably strengthened to ensure its proper coverage and make it efficient.

The Targeted Public Distribution System does not however adequately cover the indigent senior citizens who have no income of their own and none to take care of them in the village. I propose to launch a new scheme, "Annapurna" in 1999-2000, to provide food security to such persons. "Annapurna" will provide 10 kg. of foodgrains per month free of cost to all indigent senior citizens who are eligible for old age pension but are presently not receiving it and whose children are not residing in the same village. The number of persons benefitting from the scheme will not for the present exceed 20% of the old age pensioners within that State. The Gram Panchayat will be required to identify, prepare and display a list of such persons after giving wide publicity.

Health Care: The expansion and improvement of health infrastructure and services are key goals set out in the Special Action Plan announced by the Prime Minister. While an extensive network for primary health care has been created in most rural areas, inadequate community participation and supervision has constrained use of these facilities to much below their capacity. Our goal is to integrate and synergise the existing programmes for health care, family welfare, rural development and related areas in different Central Ministries and to deploy the available resources so that every household secures ready access to both primary health care and family welfare services. The Central Government will provide funds to such Gram Panchayats that come forward with their own contribution to set up primary health care facilities in their respective areas. This will match similar assistance from the concerned State Government.

Education: Access to primary education is critical for empowering people. Several States have recorded considerable success with their respective models of education guarantee schemes. I propose to implement an Education Guarantee Scheme at the national level. The aim will be to provide an elementary school in every habitation, which does not have one within a radius of 1 km. Initially, the local community would provide the premises and select a local person as a part time teacher. Teaching material and other assistance will be provided by the Central and the State Governments, while Gram Panchayats will mobilise contribution from the local community in cash and kind for running the school for at least two years. After the school has functioned successfully for two years, it will be upgraded on a permanent basis. At least 1.8 lakh such schools will become operational during the next three years of the Ninth Plan. The resources available under the existing Centrally sponsored education schemes will be mobilised

to support this important initiative. This initiative will provide an opportunity to the rural poor, especially those belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes to secure education for their children. This is the first and most important step towards their empowerment.

Employment: At present, a variety of self-employment and wage employment schemes are in operation. To enhance the effectiveness of these schemes in generating income-earning opportunities for the rural poor, Government will follow a four-pronged strategy with the common theme of ensuring greater involvement of Panchayati Raj institutions:

- The existing scheme of Jawahar Rozgar Yojana will be modified to ensure that all funds are placed at the disposal of Gram Panchayats for creation of rural infrastructure. They will have the sole authority for preparation of annual action plans and their implementation, including the power to execute works with the approval of the Gram Sabha. The modified scheme will be called "Gram Samridhi Yojana".
- * The wage employment programme of Employment Assurance Scheme will be implemented at the district/block levels, with the selection of works being decided by the Zila Parishads in consultation with the other elected representatives. The Employment Assurance Scheme presently operates through out the country. We will give special priority to areas suffering from endemic labour exodus.
- * The Gram Panchayat will maintain a live employment register available to the Gram Sabha and public for scrutiny. To ensure that the funds under the wage employment schemes are spent with the active involvement of the elected Panchayati Raj institutions, it is proposed that while 80% of funds would be released to implementing agencies as per normal procedure, the remaining 20% will be released as an incentive only if the State has put in place elected and empowered Panchayati Raj institutions.
- * The plethora of self-employment programmes for the rural poor will be merged into a single programme called "Swaran Jayanti Gram Swa-Rozgar Yojana", which will have greater participation of the Gram Panchayats. This will enable the implementing agencies to have greater flexibility in execution to meet the needs of the local people.

These schemes will largely benefit the poor and the unemployed youth in the rural areas, especially those belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

Shelter: The rural housing shortage at the beginning of 1997-98 was estimated at nearly 140 lakh units, which included shelterless households and those with only kutcha dwellings. Government's priority will be to provide shelter to all shelterless poor households by the end of the Ninth Plan. The task of upgradation of kutcha dwellings of poor households will be completed by the end of the Tenth Plan. Furthermore, to ensure integrated provision of shelter, sanitation and drinking water, we propose to launch a comprehensive "Samagra Awas Yojana", which will embrace existing programmes including Indira Awas Yojana.

18. The National Human Development Initiative will go a long way in empowering the weakest sections of the population and improving the quality of rural life. This will minimise the rural-urban disparities. The effectiveness of this initiative will depend critically on the extent to which the Gram Panchayat, as an elected body, can assume a pivotal role in implementing the various components of the programmes. I propose to declare 1999-2000 as the "Year of the Gram Sabha" to affirm our resolve to set the process of decentralised democracy in motion, with human development as the core objective of planning.

Housing

- 19. Turning to shelter in urban areas, we have already taken major steps for encouraging housing development, including repeal of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act. To improve the flow of credit for housing I propose the following measures:
 - * To develop the primary and secondary market for housing mortgages, it is necessary to simplify the present legal provisions for foreclosure and transfer of property. I propose to make necessary changes in the foreclosure laws in the housing sector through amendments in the National Housing Bank Act.
 - * To strengthen housing finance companies, I will be proposing changes in the tax treatment of the income earned on non-performing assets.
 - * To enhance the availability of banking funds to the housing sector, RBI will be advising scheduled commercial banks to lend up to 3% of their incremental deposits for housing finance.

- National Housing Bank is implementing the Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme for which I announced a target of 1 lakh dwelling units last year. Encouraged by the satisfactory response to this scheme, I propose to increase this target by 25% to 1.25 lakh dwelling units during 1999-2000.
- * The National Housing Bank has proposed a scheme, which entails a reduction in the interest rates for small borrowers. The scheme will be available in towns where Urban Land (Ceiling and Regulation) Act is not applicable. We will provide necessary support to NHB for this purpose. The details of the scheme would be announced by NHB.
- 20. The development of housing in urban areas also depends heavily on the quality of urban services. Many of our municipal bodies are at present financially too weak to provide basic services. To encourage these bodies to improve their creditworthiness in financial markets, I propose to accord tax-free status to a limited amount of municipal bonds issued each year. A little later, I shall be announcing far reaching tax initiatives to promote housing.

Industry and Infrastructure

- 21. I am deeply conscious that the last two years have been difficult for Indian industry in the context of growing integration with the world economy and the inevitable uncertainties of the global market place. But we should also be proud of the way Indian industry has surmounted difficult challenges and produced world-class winners in a number of fields such as information technology and pharmaceuticals. The process of corporate and industrial restructuring in the face of new challenges is inevitable. To help this transition, I shall be announcing important tax initiatives to facilitate corporate mergers and amalgamations.
- 22. The Industries (Development and Regulation) Act will be reviewed and amended so that the primary focus is shifted to development of industry rather than its regulation.
- 23. The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act has become obsolete in certain areas in the light of international economic developments relating to competition laws. We need to shift our focus from curbing monopolies to promoting competition. Government has decided to appoint a Committee to examine this range of issues and propose a modern Competition Law suitable for our conditions.

- 24. The Prime Minister's Advisory Council on Trade and Industry has made important recommendations regarding knowledge-based industries. The pharmaceutical industry is one of the important knowledge-based industries where we have comparative advantage. We must strengthen our drug industry's research and development capabilities. Government has decided to set up two High Level Committees to review the present drug policy so as to reduce the rigours of price controls where they have become counter-productive and also to identify required support to Indian pharmaceutical companies to undertake domestic R&D. My colleague, the Minister of Chemicals and Fertilizers will be making a separate announcement regarding this initiative. Further, in order to promote foreign direct investment in this sector, Government has decided to permit up to 74% equity under the automatic route.
- 25. While we devote our attention to the new sunrise industries, we have not neglected established industries like textiles, which employs 380 lakh workers and accounts for about 20% of our manufacturing valued added. The Technology Upgradation Fund Scheme has been approved by the Government and will become operational from April 1999. For the next five years it will provide a substantial interest incentive of 5% on loans availed by textile units from financial institutions and banks. It will cover weaving, knitting, processing and finishing units, garment manufacturing, cotton ginning and processing and the jute industry. The scheme is being extended to include the spinning industry also.
- 26. In the National Agenda for Governance, my Government has already proclaimed our commitment to the Handloom sector for providing services, technical and marketing facilities for handloom weavers. In the area of marketing, I propose to introduce a new integrated handloom promotion scheme, Deen Dayal Hathkargha Protshahan Yojana which would encourage processing facilities, new design inputs to weavers and opening new avenues for marketing of handloom fabrics.
- 27. Government has already undertaken important legislative and other reform initiatives in key infrastructure sectors such as power, telecom, roads and ports.
- 28. The Sethusamudram Ship Canal Project will provide a shorter sea route between the Eastern and the Western ports of our country. I propose to provide funds during 1999-2000 to examine the techno-economic seasibility of this much awaited project.

Small Scale Industry

- 29. Last year, I had announced a number of initiatives to improve the availability of credit to the SSI Sector. Credit delivery to this sector continues to pose challenges to our banking sector. I propose the following initiatives to improve the delivery system for credit to SSI units:
 - The composite loan scheme of SIDBI and commercial banks is designed to ease operational difficulties of the small borrowers by providing term loan and working capital through a single window. The limit for composite loans is currently Rs.2 lakh. I propose to increase this limit to Rs.5 lakh.
 - * To simplify the computation of working capital limits of SSI units, last year I had announced that for SSI units having an aggregate turn over of Rs.4 crore, working capital limit would be fixed at 20% of the annual turnover. I propose to increase this limit to Rs.5 crore.
 - * In line with the recommendations of a high powered committee appointed by it, RBI had advised banks to delegate more powers to branch managers to grant ad hoc limits, to simplify application forms, to fix their own norms for assessment of credit requirement and open more SSI branches. These measures should ease the flow of bank credit to SSI units.
 - * To increase the outreach of banks to the tiny sector, lending by banks to non banking finance companies or other financial intermediaries for purposes of on-lending to the tiny sector is being included within the definition of priority sector for bank lending.
 - Inability to provide adequate security to banks and low recovery are often cited as a major constraint in flow of investment credit to SSI units. The problem is more acute for export oriented and tiny sector enterprises. To alleviate this problem, a new credit insurance scheme will be launched.

Science and Technology

30. "Jai Vigyan" is the tribute so aptly paid by our Prime Minister to hail the achievements of our scientists. The time has come to unleash the creative potential of our scientists and innovators at grass roots level. Only then we can make India truly self-reliant and a leader in sustainable technologies. I propose a national foundation for helping innovators all over the country.

This Fund, with an initial corpus of Rs.20 crore, will build a national register of innovations, mobilise intellectual property protection, set up incubators for converting innovations into viable business opportunities and help in dissemination across the country.

- 31. Our research institutions have the capacity to evolve new vaccines that will revolutionise the medical and health systems. We propose to set up a Technology Mission on vaccines to provide a focus to the effort.
- 32. Our country is endowed with diverse and precious genetic resources, which need to be prudently conserved and managed. Among the 18 hot spots of bio-diversity in the world, two happen to be in India, in the Eastern Himalayas and the Western Ghats respectively. To coordinate policies, research, documentation and legal protection of the country's rights in this important area, a National Bio-resources Board (NBB) will be set up under the Chairmanship of the Minister of Science and Technology.

Banking

- 33. Last year I had announced important decisions flowing from the Narasimham Committee Report on Banking Sector Reforms. Subsequently, the Reserve Bank of India has taken further follow up action. I propose to carry forward the reform process:
 - The high level of NPAs in our public sector banks continues to remain a cause of concern. The Debt Recovery Tribunals, which were set up for expeditious adjudication and recovery of debts due to banks and financial institutions, have started showing encouraging results. Government has decided to set up 5 more DRTs and 4 more Debt Recovery Appellate Tribunals. I also propose to introduce a Bill in the current session of Parliament to make certain amendments in the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act to strengthen its provisions.
 - A Working Group has recently been set up by us to devise appropriate strategies for dealing with the problem of restructuring weak banks including their NPAs.
 - * The inability of banks to enter into timely compromise settlements of chronic cases of overdue loans leads to locking up of banks' funds and long drawn litigation in recovery suits. Public sector banks will be encouraged

to set up Settlement Advisory Committees so that such chronic cases, specially those relating to the small sector, are settled in a timely and speedy manner. RBI will be issuing necessary guidelines to the banks in this regard.

* Our banks are required to observe RBI norms for maintaining provisions against doubtful and non-performing assets. These norms have been strengthened in recent years. To assist banks to come up to international standards of prudential norms I shall be announcing certain changes in the tax deductibility of provisions made.

External Sector

- 34. To strengthen our external payments situation, we need to revitalise our exports and encourage more non-debt inflows in the form of foreign investment. The following steps will be taken:
 - * The existing scheme of export credit in foreign currency is being revamped to make available pre-shipment and post-shipment credit at internationally competitive rates and bring about major simplification of procedures. The RBI will separately announce the details.
 - * Studies show that our exporters are handicapped by high transaction costs related to foreign trade licensing, tax procedures and the banking system. I am establishing a high powered committee under the Revenue Secretary to go into this problem and make concrete recommendations for reduction in such transaction costs within three months.
 - In order to make inflows of foreign direct investment hassle free, the Government has decided to expand the list of automatic approvals covering important industrial and services sectors. The expanded list will be announced separately by the Minister of Industry. Wherever FIPB clearance is required, henceforth FIPB will give the decision within 30 days.
 - * There have been complaints about slow implementation of foreign direct investment (FDI) approvals. To ensure that such approvals are quickly translated into actual investment inflows and projects, Government has decided to create a Foreign Investment Implementation Authority (FIIA) within the Ministry of Industry, which may also include representatives of State Governments.

- Households and various charitable and religious institutions hold a huge amount of gold in the country. These are idle assets earning no income for the holders, who often incur costs to ensure security. This is a somewhat anomalous situation considering that the country spends thousands of crore worth of foreign exchange each year to meet fresh demand for gold holding. To mobilise this idle gold, I propose a new Gold Deposit Scheme. Selected banks will be permitted to accept gold deposits and issue interest bearing certificates or bonds which, on maturity, can be reclaimed in gold. This would free depositors from the problems of storage, movement and security for the gold in their possession, while providing them with a regular source of income. For the country, by recycling idle gold, we should be able to reduce our dependence on imported gold. To encourage this process, I propose to exempt the interest on the gold deposit bonds/certificates from Income Tax and the value of assets deposited in the gold deposit scheme from Wealth Tax. Furthermore, any capital gains made on these gold bonds/certificates through trading or at redemption will be exempt from capital gains tax. I would also urge all State Governments to consider exempting movement of gold covered under the scheme from octroi, sales tax, stamp duty and similar levies. I must point out that the scheme will not enjoy amnesty. The Reserve Bank will take necessary steps to implement the scheme.
- In my last Budget, I had proposed a set of initiatives to strengthen the participation of Non-Resident Indians (NRIs) in the development of our country. Encouraged by their response, I now propose a few more initiatives:
- We shall extend the facility of automatic approval for investment up to 100% by NRIs/OCBs for all items, except those which attract notified FDI equity caps, or compulsory licensing or public sector reservation under the Industrial Policy or are-reserved for the small scale sector.
- Our major stock exchanges have screen-based automated trading in securities. It is now technically possible for them to open trading terminals abroad, which would facilitate the participation of NRIs in our capital markets. I have asked the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to work out the modalities for this purpose.

The existing RBI approval mechanism for NRI investment in Indian mutual funds will be simplified to a post-factoreporting mechanism.

Capital Market

- 35. A vibrant capital market is essential for providing the much-needed funds for our infrastructure sector. Infrastructure projects need long term funds, which, in turn, require a deep and well-functioning debt market. With a view to modernising the debt market and introducing paperless trading in this segment also, Government proposes to abolish stamp duty on transfer of debt instruments within the depository mode.
- 36. Lately, there has been considerable debate on the importance of good governance of Indian corporates. It is increasingly being realised that if investors have to be drawn back to the capital market, companies have to put their houses in order by following internationally accepted practices of corporate governance. This is necessary to enhance investor confidence. To help promote this trend, I propose to institute a National Award for Excellence in Corporate Governance.
- 37. The Deepak Parekh Committee appointed by the UTI has made wide-ranging recommendations, including for restructuring of the US-64 scheme and for granting tax incentives. We are taking necessary action. I will come to the tax incentives shortly. The details of the restructuring are being announced separately in a press release. This should lift the cloud of uncertainty from the capital market and restore confidence.
- 38. My tax proposals will also greatly strengthen mutual funds and thereby help bring small retail investors back into the capital market. It has also been decided to set up a joint mechanism between SEBI and the Department of Company Affairs for taking stringent action against unscrupulous promoters who raise money from investors and misutilise them.

Expenditure Management

- 39. The high rate of growth of non-developmental expenditure by Government is a growing and critical source of concern. I propose the following initiatives:
 - * The most effective and lasting solution to this problem is to begin the process of downsizing Government. We are making an immediate beginning by abolishing four Secretary-level posts through a process of merger and rationalisation of Central Government departments. This will take effect on April 1, 1999.

- * To carry this process forward in a systematic way towards reducing the role and the administrative structure of the Government, we will constitute an Expenditure Reforms Commission headed by an eminent and experienced person.
- * In preparation for the next Budget, I propose to initiate a system of Zero Base Budgeting.
- * To promote transparency and curb the growth of contingent government liabilities, Government has decided to establish a Guarantee Redemption Fund with an initial corpus of Rs.50 crore. I encourage all State Governments to set up similar Funds.

Public Sector Reform/Disinvestment/Privatisation

- 40. Government's strategy towards public sector enterprises will continue to encompass a judicious mix of strengthening strategic units, privatising non-strategic ones through gradual disinvestment or strategic sale and devising viable rehabilitation strategies for weak units.
- 41. The disinvestment programme of the Government draws primarily upon the recommendations of the Disinvestment Commission. The Commission has so far submitted 8 Reports containing recommendations for 43 Public Sector Enterprises (PSEs). These recommendations are in various stages of implementation. Government will be referring more PSEs to it for its valued opinion. In 1999-2000, I propose to raise Rs.10,000 crore through the disinvestment programme. This will help the Government to fund the requirements of social and infrastructure sectors. Equally important, it will lead to improvements in productivity and profitability of these enterprises and also to the further development of domestic capital markets.
- 42. Government have been providing budgetary support to Central PSEs for rationalising manpower under the Voluntary Retirement Scheme (VRS). However, such assistance has generally been restricted to loss making enterprises. There are a number of enterprises which are marginally profit-making and which need to reduce manpower to remain viable but do not have the resource to finance such rationalisation exercises. Government would encourage such enterprises to raise money from banks against Government guarantees and interest subsidy.
- 43. In order to reduce the burden on budget on account of the implementation of VRS, Government will also encourage PSEs to issue bonds to the workers opting for VRS. Government will

guarantee the repayment of such bonds and also reimburse fully the interest payments. RBI will be requested to issue necessary instructions to banks to accept bonds as collateral for loans to workers who may need assistance.

- 44. The need for timely and reliable statistics for policy formulation and planning cannot be over emphasised. There is reason to believe that with progressive dismantling of the system of economic controls, the quality of data flows has weakened. Government has decided to establish a National Statistical Commission to critically examine the deficiencies of the present statistical system with a view to recommending measures for a systematic revamping of the system.
- 45. We stand today at the edge of the second millennium. We must, therefore, prepare for the opportunities and challenges of the next century and millennium. It is time to seriously debate and decide on the second generation reforms that we must put in place to make India economically strong and fully capable of competing successfully in the evolving world order. To further this process, I plan to bring a discussion paper before Parliament before the end of this Budget Session. My goal is to help build a consensus on the basic issues so that we can act more decisively to raise the growth in income, output and employment in our economy to a higher, sustainable level.

Revised Estimates for 1998-99

- 46. The non-Plan expenditure has increased by Rs.17,616 crore. There is a shortfall of Rs.3,631 crore under Plan. The normal non-Plan expenditure of the Government departments has increased only by Rs.2,539 crore. The other increases are on account of loans to States and UTs against net Small Savings collections, Rs.9,588 crore, pension, Rs.2,711 crore, interest payments, Rs.2,248 crore, and postal deficit, Rs.530 crore.
- 47. Net tax revenues for the Centre are estimated at Rs.1,09,537 crore against Rs.1,16,857 crore budgeted, reflecting a shortfall of Rs.7,320 crore. The shortfall is mainly due to lower customs revenue on account of both lower volume and unit-price of imports and lower excise revenue resulting from low industrial growth. Disinvestment receipts are expected to be Rs.8,000 crore against Rs.5,000 crore budgeted.
- 48. The fiscal deficit is thus likely to increase to 6.5% of GDP from the budget target of 5.6% on the basis of comparable GDP estimates. However, if the increase over budget in small savings loans to States and Union Territories is excluded, the adjusted fiscal deficit would be 5.9%.

Budget Estimates for 1999-2000

49. In the budget estimates for 1999-2000, the total expenditure is estimated at Rs.2,84,003 crore, of which Rs.77,000 crore is for Plan and Rs.2,07,003 crore for non-Plan.

Plan Expenditure

- 50. The budget support for Central, State and UT Plans has been placed at Rs.77,000 crove, marking an increase of Rs.8,629 crore over revised estimates 1998-99. Following the direction of the Prime Minister, the Plan for 1999-2000 focuses on basic human development needs such as education, health care, social welfare, housing, and water supply. Thus, out of the total Gross Budgetary Support of Rs.44,000 crore for the Central Plan 1999-2000, Rs.31,035 crore has been provided to 18 Ministries/Departments covered by the Prime Minister's Special Action Plan. Total Central Plan outlay at Rs.1,03,521 crore will be more by Rs.15,039 crore from the last year's level of Rs.88,482 crore. Gross budgetary support for the Central Plan is being enhanced from Rs.38,263 crore in the revised estimates 1998-99 to Rs.44,000 crore.
- 51. Compared to revised estimates 1998-1999, outlay for Plan programmes has been significantly increased in certain priority sectors. For example, the increase is 34.5% in the Agriculture and Allied Activities and 21.9% in Social Services.
- 52. Central Plan assistance to States and Union Territories in 1999-2000 is placed at Rs.33,000 crore as compared to Rs.30,108 crore in the revised estimates 1998-99. Assistance for Basic Minimum Services and Slum Development Schemes is proposed to be enhanced from Rs.3,684 crore to Rs.4,043 crore.
- 53. Last year, I had announced a non-lapsable pool for the North East. I am glad to inform you that we have already released Rs.98 crore for projects in the North East out of the savings from the budget of different Central Ministries.

Non Plan Expenditure

54. Non-Plan expenditure in 1999-2000 is estimated to be Rs.2,07,003 crore compared to Rs.2,13,541 crore in revised estimates 1998-99. This would have actually been Rs.2,32,003 crore but for a change in the system of accounting of loans to States and UTs against net Small Savings collections with effect from 1.4.99. The changeover, which is in the interest of transparency and viability of the Small Savings schemes, is being made in deference to a suggestion in the Inter State Council in December 1998 on delinking the small savings from Central

Government's fiscal deficit concerns. A Committee set up under the chairmanship of Shri R.V. Gupta has gone into the issue. Based on the Committee's recommendations and with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India, the transactions will now be under a newly created National Small Savings Fund in the Public Account, which will reflect the Treasury Banking nature of these operations. A copy of the Committee's report is being placed in the library of the Parliament for Hon'ble Members' information.

- 55. Major items of increase in non-Plan expenditure are Interest payments, Rs. 10,752 crore, Defence expenditure, Rs. 4,494 crore, and grants to States, Rs. 3,621 crore. A provision of Rs. 1,735 crore has been made for non-Plan loans to public sector enterprises mainly for payment of salaries and wages to the employees of sick and convalescent PSUs.
- 56. Rs.45,694 crore are being provided for Defence expenditure against Rs.41,200 crore in revised estimates 1998-99. Further need based budgetary support will be provided during the course of the year.

Revenue Receipts

57. Before I proceed to detail my tax proposals, I would like to highlight the position of fiscal deficit in 1999-2000, if the existing rates of taxes and tariffs are continued. Gross tax revenues would then be Rs.1,67,526 crore and the Centre's net tax revenue would be Rs.1,22,730 crore. Non-tax revenues are estimated to increase from Rs.48,128 crore in revised estimates 1998-99 to Rs.50,475 crore this year. The net revenue receipts for the Centre, including non-tax receipts, would increase from Rs.1,57,664 crore in revised estimates 1998-99 to Rs.1,73,205 crore in 1999-2000. After taking into account receipts of Rs.10,000 crore from disinvestment of equity in public sector enterprises, the fiscal deficit would be Rs.89,713 crore. This is unacceptably high. I shall now come to my proposals to reduce the deficit.

भाग ख

- 58. महोदय, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।
- 59. मैं अप्रत्यक्ष करों से शुरु करुंगा और इसमें उत्पाद शुल्क पहले है। अप्रत्यक्ष करों की विविध दरें सामान्यतः गलत-वर्गीकरण, कर-अपवंचन और बोझिल मुकदमेबाजी का मुख्य कारण मानी जाती हैं। यह अनेकरूपता संसाधनों के अकुशल आबंटन को भी प्रोत्साहित करती है। विश्व में 100 से अधिक देश अब मूल्य विधित कर (वैट) के लाभ प्राप्त कर रहे हैं और प्रत्येक मामले में दरों की संख्या काफी कम है।
- 60. मैंने अपने पिछले बजट में कर संरचना को युक्ति-संगत बनाने की समग्र-आवश्यकता का स्पष्ट रूप से संकेत दिया था तािक दरों की अनेकरूपता को कम किया जा सके और "मेरिट" दर तथा "डिमेरिट" दर के साथ केन्द्रीय दर निर्धारण सुनिश्चित हो सके। हमारे अधिकांश प्रमुख उद्योग संधों ने भी तिहरे दर की उत्पाद शुल्क संरचना की मांग की है।
- 61. मेरे आज के उत्पाद शुल्क प्रस्ताव अधिकांशतः मेरे उस इरादे को पूरा करते है जिसकी घोषणा 9 महीने पहले की गई थी। विशेष रूप से मैं वर्तमान 11 बड़ी यथामूल्य दरों को कम करके 3 करने का प्रस्ताव करता हूँ अर्थात् 16% की केन्द्रीय दर, 8% की 'मेरिट' दर और 24% की 'डिमेरिट' दर। इसे प्राप्त करने के लिये मैं यह प्रस्ताव करता हूँ:-
 - 5%, 10% और 12% की वर्तमान दरों का 8% की वर्तमान दर में विलय ।
 - वर्तमान 13%, 15% और 18% दरों का विलय कर 16% की एक नई दर बनाना और
 - विद्यमान 25% की दर के स्थान पर 24% की एक नई दर निर्धारित करना।

माननीय सदस्यगण इस बात को देख सकते हैं कि मैने पूर्व घोषित 18 प्रतिशत की केन्द्रीय दर को कम करके 16 प्रतिशत कर दिया है। इसका अर्थ, कम लागत एवं कीमत। यह एक सुखद संयोग है कि यह दर पाटिलपुत्र जो मेरा जन्म-स्थान भी है, के महान आचार्य कौटिल्य द्वारा सुझाई गयी 1/6(षड्भाग) दर के लगभग समान है।

- 62. परन्तु इस किंटन वर्ष में राजस्व की स्थिति को देखते हुए, मैं 30% और 40% की दर वाली वस्तुओं पर 24% की दर के ऊपर 6% और 16% के अधिभार (उत्पाद का विशेष शुल्क) के दो रतर निर्धारित करना चाहता हूँ। इस प्रकार इन वस्तुओं पर कुल उत्पाद शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पेट्रोल पर 32% की कर दर जारी रहेगी। अधिभार संरचना इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि भविष्य में सरकार उसे धीरे-धीरे कम करके 24% की 'डिमेरिट' दर पर ले आयेगी।
- 63. इन परिवर्तनों के फलस्वरूप अधिकांश वस्तुओं के लिये उत्पाद शुल्क दरें कम होंगी या मामूली रूप से 1% प्वाइंट बढ़ाकर उन्हें सम्मयोजित किया जाएगा। मशीनरी और पूंजीगत मालों के एक बड़े क्षेत्र में जहां मूल दर 13% से बढ़कर 16% तक हो रही है, मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि ऐसे उत्पादों पर उत्पाद शुल्क क्रेताओं के मामले में आशोधित मूल्य योजित कर योजना (मोडवेट) क्रेडिट के योग्य होगा। इसके अलावा पूंजीगत माल क्षेत्रक को सहायता पहुंचाने के लिये मेरे सीमा शुल्क प्रस्तावों में दीर्घ काल से चली आ रही विसंगतियों, जिनके कारण वड़ी सामग्रियों, इस्पात पर शुल्क दर तैयार पूंजीगत मालों की शुल्क दर से अधिक है, को दूर करना है। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूँगा कि उत्पाद शुल्क कर संरचना का यह बड़ा सुधार मोटे तौर पर राजस्व निष्प्रभावी है। समग्र रूप से यह उद्योग पर अतिरिक्त कर बोझ नही डालता। मुझे विश्वास है कि इस बड़े सुधार से उत्पादकता, विकास और रोजगार में तेजी आएगी।
- 64. अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपने अगले प्रस्ताव पर आता हूँ। मैं उच्च गति-डीजल तेल (एच.एस.डी.) पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर अतिरिक्त राजस्व जूटाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस समय कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय एवं स्वदेशी मुल्य असामान्य रूप से कम हैं और ऐसा महसूस किया जाता है कि इस वस्तु के माध्यम से कुछ अतिरिक्त राजरव अर्जित करना संसाधन जुटाने का एक साम्यिक तरीका होगा। मैं आयातित एवं स्वदेशी एच,एस.डी. पर प्रति लीटर 1 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ जिसका राजस्व संपूर्ण रूप से केन्द्र को प्राप्त होगा। इस शुल्क के लिये मैं आधा हिस्सा ग्रामीण विकास एवं सामाजिक क्षेत्रकों में किये जाने वाले कार्यों हेतु आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस शुल्क का 50 पैसे का अन्य हिस्सा तथा 2.6.1998 से लगाए गए 1 रुपये प्रति लीटर का शुल्क सांविधिक उपकर में परिवर्तित किया जाएगा और केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरित किया जाएगा। निधि का 30 प्रतिशत राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए राज्य सड़कों को हस्तान्तरित किया जाएगा। बकाया निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गी एवं एक्सप्रेस मार्गी के विकास एवं अनुरक्षण रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण और बिना कर्मचारी वाले रेलवे क्रासिंगों पर रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए किया जाएगा। इससे 1999-2000 के लिए रेलवे मंत्रालय के आयोजना संसाधनों का अन्तराल दूर होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि हम वर्ष में अतिरिक्त उत्पाद शूल्क के रूप में 4591 करोड़ रुपये और स्वदेशी रूप से उत्पादित एवं आयातित एच.एस.डी. पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के रूप में 363 करोड़ रुपए की धनराशि का संग्रहण कर सकेंगे। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एच.एस.डी. के मूल्य में इससे होने वाले परिवर्तनों की घोषणा करेगा जिसे आज की मध्य रात्रि से लागू किया जाएगा। इससे काफी हद तक 13 मई, 1988 के संकल्प में परिलक्षित संसद की इच्छा का सम्मान भी हो सकेगा जिसमें पैट्रोल और डीजल पर उत्पाद और सीमा शुल्कों का एक हिस्सा सड़कों के विकास के लिए संसाधन जुटाने के लिए निर्धारित करने की परिकल्पना की गयी थी।

- 65. पिछले बजट में विनिर्माण यूनिटों के लिये "मोडवेट" समायोजन को 95% पर रखा गया था। मैं "मोडवेट" दावों पर इस सीमा को हटाने और 100% पुनः बहाल करने का प्रस्ताव करता हूँ।
- 66. अध्यक्ष महोदय मेरे बजट प्रस्तावों में लघु उद्योग क्षेत्रक के लिये एक पैकेज भी है जिसमें निम्मलिखित घटक शामिल हैं:
 - भौन्दर्य प्रसाधन, रेफ्रीजरेशन और वातानुकूलन उपस्कर का विनिर्माण करने वाले यूनिटों के लिये विशिष्ट उत्पाद शुल्क रियायत स्कीमों के अंतर्गत मैं यह प्रस्ताव करता हूँ: पात्रता मानदण्ड के अंतर्गत 50 लाख रुपये के कारोबार को दुगुना करके 100 लाख रुपये करना, शुल्क मुक्त छूट रलैब को 15 लाख रुपये से दुगुना करके 30 लाख रुपये करना और सामान्य दरों की तुलना में आधे शुल्क के लिये योग्य स्वीकृतियों के मामले में 15 लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना ।
 - मैं भूती धागा तैयार करने वाले छोटे यूनिटों के लिये लघु उद्योग छूट सीमा का लाभ देने का प्रस्ताव करता हैं।
 - मैं ग्लेज्ड टाइलों की छपाई में लगे छोटे उजरती कार्य श्रमिकों के लिये उत्पाद शुल्क की छूट का प्रस्ताव करता हूँ।
 - इस समय लघु उद्योग यूनिटों को ऐसे उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की छूट प्राप्त नहीं है जो दूसरे विनिर्माता के ब्राण्ड नाम का उपयोग कर रहे हैं। मैं दूसरे विनिर्माता के ब्राण्ड नाम वाले सामान पर लघु उद्योग छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ यदि ऐसा सामान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित यूनिटों द्वारा तैयार किया जा रहा हो। स्कीम के विवरणों की घोषणा शीघ्र की जाएगी।
- 67. वर्तमान प्रक्रिया के अंतर्गत सभी विनिर्माण यूनिटों को अपने विनिर्माण परिसरों से माल की निकासी के समय उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होता है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आगे और सरल बनाने के उपाय के रूप में लघु उद्योग यूनिटों को 1.6.1999 से मासिक आधार पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की अनुमित प्रदान करने का मैं प्रस्ताव करता हूँ। प्रक्रिया के सरलीकरण का एक महत्वपूर्ण कदम होने के अलावा इस परिवर्तन से लघु उद्योग क्षेत्रक में विनिर्माण यूनिटों की भुगतान कर सकने की स्थिति में भी सुधार होगा।
- 68. फैक्ट्रियों द्वारा उत्पाद शुल्क रिकार्ड रखने की आवश्यकता के संबंध में इसी प्रकार की प्रक्रियात्मक छूट का भी मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ। अब आगे से वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक उत्पाद शुल्क का भुगतान करने वाली फैक्ट्रियों को उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रारूप में अपना रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी और उनके सामान्य कार्य संचालन के दौरान रखे गये रिकार्ड को पर्याप्त माना जाएगा। यह संशोधन 1.6.99 से लागू होगा।
- 69. इस समय अनेक ऐसी वस्तुयें हैं, जिन्हें उत्पाद शुल्क से या तो पूर्ण छूट दी गई है या रियायती उत्पाद शुल्क लगाया गया है। यह रियायतें गत समय में उस वस्तु से संबंधित तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए दी गई थीं। शुल्कों की आम दरों में कमी आने से ऐसी छूटों एवं रियायतों की आवश्यकता नहीं रह गई है। फिर भी प्रत्येक विशिष्ट मामले से संबंधित परिस्थितियों का आकलन करने और इन रियायतों को जारी रखने या समाप्त करने के प्रश्न पर सुविचारित सिफारिशें प्राप्त करने के लिये मैं एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो इन बातों की जांच करेगी और सलाह देगी कि कहां छूटें जारी रखी जानी चाहिए और कहां

उन्हें नई दर संरचना में एकीकृत किया जाना चाहिए। इसकी रिपोर्ट अगले बजट में विचार के लिये उपलब्ध होनी चाहिए।

- 70. जैसा कि माननीय सदस्यगण इस बात को जानते हैं कि उत्पाद शुल्क से तदर्थ छूट देने के लिये सरकार को शक्तियां दी गई हैं। मैं इसे व्यापक स्वविवेकाधिकार को आवश्यक नहीं समझता। अतः मैं सामरिक या गोपनीय प्रकार के सामान या चैरिटेबल प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रकार के सामान के लिये उत्पाद शुल्क की तदर्थ छूट देने की सरकार की शक्तियों को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। सीमा शुल्क के मामले में भी मैं शक्तियां इसी प्रकार समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।
- 71. अध्यक्ष महोदय, मैं अब सीमा शुल्क से संबंधित अपने प्रस्तावों पर आता हूँ। मेरे प्रस्ताव यहां अलग-अलग विचारणाओं के संतुलन को प्रदर्शित करते हैं। एक ओर हम विश्व अर्धव्यवस्था के साथ अपनी अर्थव्यवस्था के सुविचारित एकीकरण के प्रति वचनबद्ध हैं। इसमें एशियाई स्तरों तक हमारे सीमा शुल्क को क्रमिक रूप से नीचे लाना निहित है। दूसरी ओर राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता है और वास्तविकता यह है कि विश्व की अर्थ-व्यवस्था में एक वर्ष में असाधारण विक्षोभ एवं अनिश्चितता के परिप्रेक्ष्य में हमारे उद्योग को आयातों से उत्पन्न असामान्य रूप से बढ़े प्रतिस्पर्धात्मक दबाव से मुकाबला करने हेतु तैयार होना चाहिए।
- 72. महोदय, 1996-97 के बजट में 2% का एक विशेष सीमा शुक्क लगाया गया था और 1997-98 में कुछ वस्तुओं पर 3% का विशेष सीमा शुक्क पुनः लगाया गया था। यह 5% का विशेष सीमा शुक्क 31.3.1999 तक लागू है। एक अन्य चर्चा के दौरान मैने इस सदन को आश्वासन दिया था कि इस विशेष सीमा शुक्क की वैधता अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। मैं यह घोषणा करता हूँ कि 28.2.1999 से 5% विशेष सीमा शुक्क समाप्त कर दिया जाएगा।
- 73. विभिन्न संभावनाओं की सावधानीपूर्वक जांच करने और वाणिज्य एवं उद्योग के शीर्षस्थ संगठनों के साथ गहन बातचीत के बाद मैं सीमा शुल्क की वर्तमान 7 बड़ी यथामूल्य दरों को कम करके 5 मूल दरें रखने का प्रस्ताव करता हूँ। नई दरें इस प्रकार होंगी:-
 - 5% जो अपरिवर्तित रहेगी.
 - वर्तमान 10% की दर के स्थान पर 15%
 - 20% और 25% की दर का विलयन कर 25%
 - 30% और 35% दरों का विलय कर 35%,
 - 40% जो अपरिवर्तित रहेगी।
- 74. एक ऐसा उद्योग जिस पर सीमा शुक्क की विशेष कर-प्रणाली लागू होगी वह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक है। प्रधान मंत्री ने नई शताब्दी एवं सहस्राब्दि में देश के विकास के लिये इस क्षेत्रक के महत्व पर बार-बार जोर दिया है। तद्नुसार मैं इस क्षेत्रक में, अनेक महत्वपूर्ण सामग्रियों जैसे आई.सी और माइक्रो असेम्बली, भण्डारण साधन और सी.डी. रोम्स, दूरसेचार उपस्कर और ऑप्टिकल फाइबर की शुक्क दर में महत्वपूर्ण कटौतियों का प्रस्ताव कर रहा हूँ।
- 75. देश की कम न की जा सकने वाली आवश्यताओं को पूरा करने के लिये राजस्व जुटाने हेतु मैं निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर सभी वस्तुओं पर 10% की समान दर से अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।
 - कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद;
 - वे मदें जिन पर 40 प्रतिशत की दर से मूल शुल्क लगता है;

- जी.ए.टी.टी (गैट) करार के अन्तर्गत आने वाली कतिपय मदें:
- सोना और चांदी:

अधिभार के प्रभाव से मूल दर में 10 प्रतिशत तक वृद्धि होगी। इस प्रकार 5 प्रतिशत की मूल दर 5.5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की दर 16.5 प्रतिशत हो जाएगी।

- 76. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विशेष सीमा शुल्क को समाप्त किया जा रहा है और कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों को अधिभार से छूट प्रदान की जा रही है, इन उत्पादों पर प्रमावी आयात शुल्क दरें कम हो जाएंगी। यह तयशुदा समय सीमा में इन उत्पादों पर अप्रत्यक्ष करों को युक्तिसंगत बनाने की सरकार की सर्वसम्मत नीति के अनुरूप है।
- 77. उन मदों जिन पर 40 प्रतिशत की दर से मूल शुल्क लागू है, छूट प्रदान करने से संरक्षात्मक सीमा शुल्क की सर्वोच्च दर में 45 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की मामूली लेकिन स्पष्ट कमी की गई है।
- 78. अध्यक्ष महोदय, सैद्धान्तिक तौर पर मैं शृन्य सीमा शुल्क के खिलाफ हूँ क्योंिक हमारे स्वदेशी उद्योग को आमतौर पर कुछ न्यूनतम संरक्षण की आवश्यकता है। मैनें ऐसी वस्तुओं की सम्पूर्ण सूची की पुनरीक्षा की है और मैं कुछ ऐसी वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसी मदों जिन्हें पहले छूट प्राप्त थी, पर 5 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाने के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, मैं इस श्रेणी को मौजूदा 4 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।
- 79. मैं परियोजना आयातों की आयात शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बना रहा. हूँ। यौक्तिकीकरण की इस प्रक्रिया के अन्तर्गत, विद्युत उत्पादन, कोयला खनन, तेल शोधन, दूर-संचार और उर्वरक परियोजनाओं पर अब केवल 5 प्रतिशत का मामूली आधारिक सीमा शुल्क लगेगा। परन्तु उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की लागू दरें जारी रखी जाएंगी। अधिकांश मामलों में इन परिवर्तनों का निवल प्रभाव अधिक नहीं होगा। विशाल विद्युत परियोजनाएं भी इसका अपवाद होंगी।
- 80. अध्यक्ष महोदय, इस बजट में अप्रत्यक्ष करों के संबंध में किए गए विभिन्न प्रस्तावों के परिणामस्वरूप वर्ष 1999-2000 में अनुमानित राजस्व 6,234 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन संग्रहण के घटक सहित 1,17,625 करोड़ रुपये होगा।
- 81. पिछले वर्ष मैंने उत्पाद और सीमा शुल्क से संबंधित अग्रिम निर्णयन प्राधिकरण की स्थापना की घोषणा की थी। आवश्यक विधायन इस वित्त विधेयक में शामिल किया गया है। प्रत्यक्ष कर से संबंधित अग्रिम निर्णयन प्राधिकरण की तर्ज पर ही प्रस्तावित प्राधिकरण महत्वपूर्ण मुद्दों पर बाध्यकारी निर्णय देगा, ताकि इच्छुक निवेशकर्ताओं को अग्रिम रूप से अपनी शुल्क देनदारी का स्पष्ट आभास हो सकेगा।
- 82. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक 'विजन डॉक्यूमेंट' और 'सिटिजन्स चार्टर' अपनाया है, जो सम्मिलित रूप से उस भविष्य की रूपरेखा और उन सेवा मानकों को पेश करते हैं जिनकी उम्मीद सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग से की जा सकती है। चार्टर में निर्धारित सेवा मानकों के अनुपालन की बारीकी से मानीटरिंग की जा रही है। सीमा शुल्क आयुक्तों और फील्ड स्तर के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाएं और उन्हें यह भी बताया गया है कि गैर-अनुपालन की स्थिति को उनके प्रतिकूल माना जाएगा।

- 83. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्र में मूल्य-निर्धारण और लेखा परीक्षा प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और शीघ्र ही विवरणियों के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का कार्य चालू किया जाना प्रस्तावित है।
- 84. सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्कों में प्रस्तावित परिवर्तनों को कार्यरूप देने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां यथासमय सदन के पटल पर रखी जाएंगी।
 - अध्यक्ष महोदय, मैं अब प्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों की तरफ आता हूं।
- 86. अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए उदारीकरण के साथ ही औद्योगिक पुनर्संरचना की आवश्यकता भी सामने आई है तािक कम्पनियां अपने मुख्य क्रियाकलापों पर स्वयं को बेहतर ढंग से केन्द्रित कर सकें। निगमित क्षेत्रक, व्यापार पुनर्गठन के विनियमन के लिए एक लचीली राजकोषीय नीित की आवश्यकता की आवाज उठाता रहा है। इस आवश्यकता के प्रत्युत्तर में मेरा आयकर अधिनियम में व्यापक तौर पर संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि व्यापार पुनर्गठनों को पूरी तरह कर-निष्प्रभावी बनाया जा सके। कम्पनियों के समामेलन की स्थिति में प्रस्ताव को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के माध्यम से चलाए जाने की वर्तमान अपेक्षा को हटाया जा रहा है। कानूनी उपबंध में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि कर रियायतों के लिए पात्रता यह है कि सभामेलित कम्पनी में समामेलन करने वाली कम्पनी की अचल परिसम्पत्तियों का कम से कम 75 प्रतिशत हो और इस शर्त पर कि समामेलित कम्पनी कम से कम 5 वर्ष तक समामेलक कम्पनी का कारोबार जारी रखेगी। सांविधिक उपबन्ध से उपलब्ध शक्तियों के अधीन बाद में जारी किए जाने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए आय-कर अधिनियम के संशोधन के जिरए एक सामर्थ्यकारी उपबंध की व्यवस्था की जाएगी।
- 87. अलग होने की स्थिति में मेरा एक कानूनी उपबंध पेश करने का प्रस्ताव है जिससे कि संचित हानियों और खपाए न गए मूल्यहास को पृथक होने वाली कम्पनी से पारिणामिक कम्पनी के पास ले जाने की अनुमित दी जा सके। मेरा कानूनी उपबंधों में संशोधन का भी प्रस्ताव है तािक लेन-देनों के परिणामस्वरूप न तो संलिप्त कम्पनियों, न ही शेयर होल्डरों को लेन-देनों के परिणामस्वरूप में तो संहिप्त कम्पनियों, न ही शेयर होल्डरों को लेन-देनों के परिणामस्वरूप पूंजी लाभ कर देना पड़े। इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव है, कि सभी राजकोषीय रियायतें समामेलन और पृथक्कीकरण की स्थित में बची हुई अविध के लिये जारी रहें।
- 88. अध्यक्ष महोदय सरकार पूंजी बाजारों में निरन्तर छाई मन्दी से बहुत अधिक चिन्तित है। सरकार भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के संबंध में निवेशकर्ता जनता के कुछ तबकों की नकारात्मक धारणा से भी चिन्तित है। श्री दीपक पारिख की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर और इस क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा वड़ी संख्या में प्रस्तुत सुझावों पर भी गौर करने के बाद, भारतीय यूनिट ट्रस्ट में शेयरधारको के विश्वास की बहाली के लिए और आमतौर पर पूंजी बाजारों में जान डालने के लिए मैं अब एक बड़े राजकोषीय पैकेज का प्रस्ताव करता हूँ।
- 89. सर्वप्रथम मैं निवेशकों के हाथों में प्राप्त भारतीय यूनिट ट्रस्ट और म्यूचुअल निधियों से सभी आय को आय कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे न केवल कर का प्रभावक्षेत्र घटेगा वरन छोटे निवेशकों के सामने कर की अदायगी करने और ऐसे निवेशों से हासिल आय के सम्बन्ध में वापसी का दावा करने में पेश आ रही अस्विधाओं को दूर किया जा सकेगा।
- 90. वर्तमान में यदि निवेशकों के हाथ की आय पूरी तरह कर से मुक्त है तो यह आय भारतीय यूनिट ट्रस्ट या म्यूचुअल निधियों द्वारा लाभांश के वितरण की अवस्था में आयकर

अधिनियंम की धारा 115(ण) के अधीन लामांश कर के तहत आती है। नीति से हटकर और पैकेज के दूसरे घटक के रूप में, मैं यू एस-64 स्कीम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंडों की उन सभी खुली इक्विटी आधारित स्कीमों, जिनका 50 प्रतिशत से अधिक निवेश इक्विटी में है, के लिए लाभांश कर से 3 वर्ष तक छूट जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, उन म्यूचुअल फंडों जिनमें इक्विटी निवेश 50 प्रतिशत से कम है, को वितरित आय पर 10 प्रतिशत लाभांश कर देना होगा।

- 91. इन दो कर प्रस्तावों के परिणामस्यरूप, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और म्यूचुअल निधियों में निवेश अधिक आकर्षक बन सकेगा और इक्विटी आधारित स्कीमें उन स्कीमों की अपेक्षा अधिक आकर्षक बन सकेंगी जिनमें इक्विटी निवेश 50 प्रतिशत से कम है। इससे छोटे निवेशकों की पूंजी बाजार में वापसी को बढ़ावा मिलेगा और उनके विश्वास की बहाली होगी।
- 92. एक शिकायत अक्सर उठाई जाती रही है कि निवासी और अनिवासी भारतीयों के बीच शेयरों और प्रतिभूतियों के अन्तरण पर दीर्घावधिक पूंजी अनुलाभ कर की दर में भेदभाव किया गया है। निवासी भारतीयों के लिए दीर्घावधिक पूंजी अनुलाभ की वर्तमान दर 20 प्रतिशत है जो मुद्रास्फीति सूचकांक की लागत के संदर्भ में परिकलित पूंजी अनुलाभों के एक कल्पित मूल्य से जुड़ी है। परन्तु अनिवासी भारतीयों के लिए दीर्घावधिक पूंजी अनुलाभ कर की दर केवल 10 प्रतिशत है। इस शिकायत के जवाब में, अब मैं इस कानून में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं जिससे कि निवासी भारतीयों के लिए शेयरों और प्रतिभूतियों के अन्तरण पर दीर्घावधिक पूंजी अनुलाभ कर की अधिकतम दर 10 प्रतिशत पर निर्घारित की जा सके।
- 93. अर्थव्यवस्था के कुछ 'नवोदित' क्षेत्रकों में प्रबन्धन अपने कर्मचारियों को स्टॉक विकल्पों और 'स्वेट इक्विटी' की पेशकश करने की नीति अपना रहा है। ऐसे लेनदेनों का कर-निर्धारण कुछ हद तक अस्पष्ट है। अतः मेरा कानून में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह बात सन्देह से परे रहे कि ऐसे स्टॉक विकल्पों पर कर्मचारी द्वारा विकल्प के प्रयोग के समय पूर्वापेक्षा के रूप में और बाद में प्रतिभूति की बिक्री के समय पूंजी अनुलाभों के रूप में कर लगाया जाएगा। इन संशोधनों से मुझे आशा है कि ऐसे लेन-देनों से सम्बन्धित वर्तमान कानूनों में मौजूद अस्पष्ट पहलुओं को स्पष्ट कर दिया जाएगा।
- 94. उच्च तकनीकी क्षेत्रकों में तेजी लाने और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को सहायता देने के लिए जोखिम पूंजी क्रियाकलापों में अधिक निवेश करने की अत्यन्त आवश्यकता है। हाल ही में हमने समयबद्ध निवेश और न्यूनतम निधि रोध की अपेक्षा को हटाकर विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत मार्गनिर्देशों में छूट दी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ जोखिम पूंजी क्रियाकलापों के पंजीकरण और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकरण के लिए मैं मार्गनिर्देशों में सामंजस्य भी कर रहा हूँ। इससे दोनों संगठनों के पास पंजीकरण के मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित होगी। मुझे विश्वास है कि इन प्रमासों से जोखिम पूंजी स्कीम का आकर्षण बढ़ेगा और 'नवोदित' क्षेत्रकों, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के लिए अपनी निधियां लगाने की दिशा में उच्च निवल सम्पत्ति वाले निवेश का प्रेरणा मिलेगी।
- 95. अभी हाल ही में शेयरों की वापसी खरीद से सम्बन्धित लेनदेनों की अनुमित देने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया है। कानून की इस व्याख्या में कुछ अस्फब्दता है कि क्या ऐसे लेन-देनों को पूंजी अनुलाभ कर के अतिरिक्त लामांश कर के अधीन भी समझा जाएगा। इसके मद्देनजर मेरा इस कानून में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि यह बात

सन्देह से परे रहे कि शेयरों की वापसी खरीद पर शेयरधारकों को लाभांश कर नहीं देना होगा और वे केवल पूंजी अनुलाभ कर के देनदार होंगे।

- 96. अध्यक्ष महोदय, मैं अब इस बजट के एक अन्य विशेष ध्यानाकर्षण के क्षेत्र अर्थात आवास क्षेत्रक की ओर लौटना चाहूंगा। मैं इस क्षेत्रक के सम्बन्ध में राजकोषीय प्रोत्साहनों के एक व्यापक पैकेज का प्रस्ताव करता हूँ जो निम्नलिखित पर केन्द्रित है:-
 - आवास खरीदने की इच्छा रखने वाले मध्यमवर्गीय निवेशक;
 - मध्यम आय आवास परियोजनाओं के प्रमोटर; और
 - आवास वित्त कम्पनियां।
- 97. इस पैकेज के पहले घटक के रूप में, मेरा यह प्रस्ताव है कि स्वयं के कब्जे वाली सम्पत्ति के लिए ऋण पर ब्याज को 30,000 रुपए की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 75,000 रुपए की सीमा तक कर से छूट प्रदान की जाए। इस रियायत से मध्यमवर्गीय निवेशकों को अपना स्वयं का छोटा घर खरीदने के वास्ते ऋण लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- 98. इस प्रोत्साहन पैकेज का दूसरा घटक आयकर अधिनियम की घारा 80 झक के अधीन करावकाश का लाभ उठाने की आजासाय परियोजनाओं की स्कीम से संबंधित है। मौजूदा उपबन्धों में अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि रिहायशी इकाइयों का निर्मित क्षेत्र 1000 वर्गफुट से अधिक नहीं होना चाहिए। कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मुम्बई और दिल्ली को छोड़कर अन्य शहरों में भूमि की लागत सापेक्ष रूप से कम है और इसलिए इस पूंजी व्यय से निवेशक अपेक्षतया कुछ बड़े आकार की रिहायशी इकाइयों की खरीद करने में सक्षम हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया गया है कि स्वीकृत परियोजनाओं में रिहायशी इकाइयों के लिए निर्मित क्षेत्रों से सम्बद्ध उच्चतम सीमा को मुम्बई और दिल्ली को छोड़कर सभी स्थानों पर 1000 वर्गफुट से बढ़ाकर 1500 वर्गफुट कर दिया जाए। मैं इस सुझाव को स्वीकार करने और कानून में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं। इस स्कीम में आवास परियोजनाओं को आधारभूत क्षेत्र के रूप में मानने सम्बन्धी इस संशोधन से मुझे विश्वास है कि इससे छोटे शहरों में निर्माण गतिविधियों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा।
- 99. निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि आवास वित्त कम्पनियों वित्तीय रूप से सक्षम हों। वर्तमान में ऐसी वित्त कम्पनियों को संचित आधार पर ऋणों से प्राप्त ब्याज पर कर देना होता है। ऐसी आवास वित्त कम्पनियों पर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए मैं कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि ऐसी कम्पनियों की आय संचित आधार के बजाय वास्तविक आधार पर कर योग्य होगी।
- 100. बड़े शहरों में आवास चाहने वाले लोगों की संख्या का एक बड़ा भाग व्यापार क्षेत्र के कर्मचारियों से सम्बन्धित है। मैं समझता हूं कि व्यापारिक क्षेत्रक को अपने कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करना आवश्यक है तािक बड़ी संख्या में आवास निर्माण हो सके। इस भावना को ध्यान में रखते हुए मैं व्यापारिक क्षेत्रक द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए खरीद किए गए नए रिहायशी इकाइयों पर हास दर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।
- 101. मुझे आशा है कि आवास निर्माण क्षेत्रक के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों से सम्बद्ध यह सम्पूर्ण पैकेज सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के पुनरुखान के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य

करेगा। निर्माण क्षेत्रक का कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों विशेष रूप से इस्पात और सीमेंट के साथ घनिष्ठ संबंध है। निर्माण गतिविधियों में सामान्य तेजी से न केवल देश में आवासों की संख्या में बढ़ोतरी होगी बल्कि इसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आयेगी।

- 102. कुछ बैंकों में गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां बड़ी मात्रा में मौजूद होने के सम्बन्ध में कुछ हलकों में शंकाएं व्यक्त की गयी हैं। मेरा विचार है कि बैंक अपने खातों को स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने का पूरा प्रयास करें और लेखों की पारदर्शिता के सम्बन्ध में यदि कोई शंका मौजूद हो तो उसे दूर करें। अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में ऐसी राशियों पर कर कटौती का प्रस्ताव करता हूं जिसे बैंको द्वारा 'सन्देहास्पद ऋणों' के रूप में दिखाया गया है लेकिन यह किसी भी एक वर्ष में ऐसे कुल 'सन्देहास्पद ऋणों' का अधिकतम 5 प्रतिशत तक होगा। यह रियायत ऐसे 'सन्देहास्पद ऋणों' के सम्बन्ध में जिनकी पहचान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेक-सम्मत मानदंडों के अन्तर्गत की गयी है, 5 वर्षों के लिए उपलब्ध रहेगी।
- 103. मैं कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि ऋणकर्ता द्वारा सहकारी बैंक को संन्यी आधार के बजाय वास्तविक आधार पर किए गए ब्याज भुगतान पर उसे कर रियायत मिल सके। इस प्रस्ताव से ऋणकर्ताओं को कर लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी ब्याज देयता की समय पर पुनः अदायगी करने की प्रेरणा मिलेगी और तद्नुसार सहकारी बैंकों की वित्तीय दशा में सुधार की भी आशा की जा सकती है।
- 104. माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आधारभूत तथा उद्योग क्षेत्रकों से सम्बन्धित प्रस्तावों की तरफ बढ़ता हूँ।
 - मैं कृषि उत्पादों से सम्बन्धित शीत भण्डारण व्यवस्था के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80झक के अन्तर्गत करावकाश के माध्यम से राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।
 - * अधिकांश राज्य विद्युत बोर्डो की वित्तीय स्थिति अत्यधिक नाजुक है। अनेक राज्य विद्युत बोर्ड पृथक कम्पनियों को विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वित्तरण सम्बन्धी कार्य सौंपकर इस स्थिति से निजात पाना चाहते हैं। मैं दिनांक 1-4-1999 के बाद स्थापित विद्युत के पारेषण तथा वितरण कार्यों को आधार सुविधा इकाइयों के लिए उपलब्ध राजकोषीय प्रोत्साहन पाने का पात्र मानने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस प्रस्ताव से राज्य विद्युत बोर्डो की पुनर्सरचना तथा पुनर्वास कार्य में सुविधा होगी।
 - इस समय, आधारभूत संरचना क्षेत्रक तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में आयकर अिधनियम की धारा 80 झक के अन्तर्गत दी जा रही कर रियायत को निर्धारित अिधकतम अविध सीमा के अंदर उपयोग करना होता है। कर रियायत के सम्बन्ध में दी गई यह अधिकतम अविध क्षेत्रक-वार भिन्न-भिन्न होती है। इसमें एक रूपता लाने के लिए, मैं आयकर अधिनियम में संशोधन लाने का प्रस्ताव करता हूं तािक अधिकतम 15 वर्षों की समयाविध में इकाइयां आधारभूत तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रकों की इकाइयों को प्रदत्त कर रियायत का उपयोग कर सकें।
 - अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के प्रित सजग हूं कि हमारी सम्पूर्ण घोषणाओं के बावजूद, पूर्वोत्तर क्षेत्र का औद्योगिक विकास हमारी आशानुरूप नहीं हुआ है। देश के इस भाग में औद्योगिकीकरण में तेजी लाने के लिए मैं ऐसे सभी उद्योगों में 10 वर्ष का करावकाश प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास केन्द्रों, औद्योगिक आधारभूत विकास निगमों तथा अन्य विनिर्दिष्ट उद्योगों में स्थापित हैं। मैं इस देश के उद्यमियों से आग्रह करूंगा कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं तथा इस क्षेत्र में आधुनिक, उच्च मूल्यवर्धित विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करें।

105. भारतीय मनोरंजन उद्योग जिसमें फिल्म, संगीत तथा टेलीविजन साफ्टवेयर शामिल हैं, दिन-दूनी रात चौगुनी उन्नित कर रहा है। मुझे विश्वास है कि अपनी सृजनात्मक शक्ति तथा प्रतिभा के बल पर भारत विश्व में मीडिया के क्षेत्रक में महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। हमने कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विकास तथा निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है और यही सफलता मनोरंजन उद्योग के उत्पादों विशेष रूप से फिल्म, टी.वी. साफ्टवेयर तथा संगीत के विकास तथा निर्यात के सम्बन्ध में भी प्राप्त की जा सकती है। इस क्षेत्रक में भारत महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो इसके लिए मैं बजट में कई उपायों को शामिल कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य इस क्षेत्रक को भी वही सुविधाएं तथा कर लाम प्रदान करना है जो धारा 80जजग के अन्तर्गत मालों और तिजारती वस्तुओं के निर्यात के लिए उपलब्ध हैं।

106. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मनोरंजन उद्योग को 'दिल से' सहायता प्रदान करने का हमारा प्रयास रहेगा और मुझे पूरी आशा है कि मनोरंजन उद्योग को सरकार से अब यह नहीं कहना पड़ेगा कि 'हम आपके हैं कौन'।

107. अध्यक्ष महोदय, हम सभी इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक हमारे भविष्य का क्षेत्रक बनने वाला है। आसन्न संकट जो इस क्षेत्र के ऊपर मंडरा रहा है, वह "वाई 2 के" समस्या से जुड़ा है जो चालू कैलैंडर वर्ष के अन्त में हम पर प्रहार करेगा। मेरा यह समझना है कि निगमित क्षेत्रक को इन खतरों की अच्छी तरह से जानकारी नहीं है जो इस समस्या के कारण उनके सामने खड़े हैं। ऐसी परिस्थितियों में, व्यापारिक क्षेत्रक को "वाई 2 के" समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन्होंने अपनी व्यवस्था को "वाई 2 के" की अनुगामी बनाने के लिए जो सम्पूर्ण व्यय किया है उसे आगामी वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में मानने की स्वीकृति दी जाए। व्यापारिक क्षेत्रक से मेरा आग्रह है कि वे इस रियायत का फायदा उठाएं तथा अपने साफ्टवेयर प्रणाली में मौजूद दोष को दूर करने का हर संभव प्रयत्न करें नहीं तो उनका बहुमूल्य आंकड़ा आधार पूर्णतया गड़बड़ा जाएगा।

108. मौजूदा कानून के अन्तर्गत, 31-3-2000 तक निगमित घरानों को अपने अन्तरंग अनुसंधान तथा विकास पर किए गए व्यय की 125 प्रतिशत की भारित कटौती उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यह अवधि किसी भी कम्पनी के लिए अपने अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने हेतु काफी कम है। मैं अन्तरंग अनुसंधान तथा विकास पर प्रदान की जाने वाली इस रियायत को 31-3-2005 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा, मैं अनुसंधान तथा विकास की अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों को सींपी गयी परियोजनाओं के लिए इसी प्रकार व्यय की 125 प्रतिशत भारित कटौती की रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था में, भविष्य उनका है जो प्रौद्योगिकी के विकास में अग्रणी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मैं निगमित क्षेत्रक से आग्रह करूंगा कि वे इस सुविधा का अधिकतम सीमा तक उपयोग करें।

109. पिछले कुछ वर्षों में, प्रत्यक्ष कर विभाग ने राष्ट्रीय कर आधार को विस्तृत करने के लिए समन्वित प्रयास किए हैं। सम्भावित करवाताओं की पहचान करने के लिए, "छह में एक" योजना को वर्ष 1998-99 में 35 शहरों में विस्तारित किया गया। इस योजना से काफी सन्तोषप्रद परिणाम निकले हैं। इस योजना को संचालित करने के परिणामस्वरूप, एक वर्ष की समयाविध में करवाताओं की संख्या 120 लाख से बढ़कर 140 लाख हो गयी। विभाग का यह आकलन है कि और अधिक करवाताओं को पंजीकृत करने की काफी गुंजाइश है। इस योजना के अनुकूल परिणामों को देखते हुए, मैं अब इस योजना का ऐसे 19 और शहरों में विस्तार करने का प्रस्ताय करता हूं, जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है।

110. पिछले बजट से आयकर विभाग ने करदाता आवेदकों को 'पैन' (स्थायी खाता संख्या) जारी करने का अभियान चलाया है। इस योजना के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया काफी उत्साहवर्धक

रही है और हमें 168 लाख तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अपेक्षित 'पैन' पहले ही 75 लाख करदाताओं को जारी किए जा चुके हैं और हमें विश्वास है कि शेष आवेदन पत्रों का आगामी कुछ महीनों में निपटान कर लिया जाएगा।

- 111. अध्यक्ष महोदय, मैं उन प्रस्तावों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो समाज के उन वर्गों के लिए हैं जिनके संबंध में सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, मैं वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए की गयी कटौती को मौजूदा 10,000 रुपए के रतर से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने और विशिष्ट बीमारियों के इलाज के संबंध में कर कटौती को 60,000 रुपए तक के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस बात को देखते हुए कि चिकित्सा एवं अस्पताली खर्च में वृद्धि हो गयी है और जीवन की अविध में भी सुधार हुआ है, सामान्य बीमा उद्योग का इरादा मेडिक्लेम पालिसी के अन्तर्गत बीमित धनराशि की उच्च सीमा वर्तमान 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने और कवरेज के लिए मौजूदा 75 वर्ष बढ़ाकर 80 वर्ष करने का है। दूसरा, कामकाजी महिलाओं की हॉस्टल परियोजना के संबंध में किया गया व्यय आयकर अधिनियम की धारा 35कग के अंतर्गत कर योग्य आय से कटौती के योग्य होगा। तीसरा, मैं विभिन्न शौर्य पुरस्कार विजेताओं द्वारा प्राप्त पेंशन तथा उनके उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त परिवार पेंशन को आय कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।
- 112. अध्यक्ष महोदय, अब मैं अब प्रत्यक्ष करों पर अपना अन्तिम प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ, मेरे सामने एक ओर राजस्व एवं राजकोषीय घाटों को नियंमित करने और दूसरी ओर बढ़ते हुए विकास व्यय को पूरा करने का कठिन काम है। मैं इस कार्य को पूरा करने का प्रस्ताव करता हूँ और साथ ही समान रूप से इस बोझ की साझेदारी सुनिश्चित करता हूँ। मैं समाज के उन वर्गों से ही एक छोटी मांग कर रहा हूँ जिनके पास भुगतान करने की क्षमता है जबिक कम आय वालों को इससे छूट दे रहा हूँ। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सभी कम्पनी करों पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगाने और साथ ही कर निर्धारितियों के अन्य सभी वर्गों पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूं। व्यष्टियों और अविभाजित हिन्दू परिवारों के संबंध में, इस अधिभार की प्रयोज्यता उन लोगों तक सीमित हैं जिनकी कुल आय 60,000 रुपए अथवा अधिक है। वास्तव में, इस अधिभार का तात्पर्य 20 प्रतिशत के स्लैब में 2 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत के स्लैब में 3 प्रतिशत की सीमान्त बढ़ोतरी करना होगा इससे 10 प्रतिशत की स्लैब में मौजूदा दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह अस्थाई अधिभार के रूप में है। मुझे विश्वास है कि सदन और हमारे नागरिक उन परिस्थितियों को समझेंगे जिनके अंतर्गत मुझे यह प्रस्ताव पेश करना पड़ा।
- 113. निष्कर्ष रूप में, अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष करों के संबंध में इस बजट में किए गए विभिन्न प्रस्तायों के फलस्वरूप वर्ष 1999-2000 में 59,235 करोड़ रुपए का राजस्य प्राप्त होने का अनुमान है जिसमें 3100 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त संसाधन जुटाना भी शामिल है।
- 114. अब मुझे अपने माननीय सहयोगी संचार मंत्री की तरफ से कुछ कहना है। डाक सेवा बड़े पैमाने पर रोजगारपरक है और वेतन तथा भत्ते डाक विभाग के प्रचालनात्मक खर्चों का एक मुख्य हिस्सा होते हैं। इसलिए, कुछ डाक सेवाओं के लिए शुल्क में संशोधन अपरिहार्य हो गया है। तथापि, आम आदमी के हित में और समाचार तथा सूचना के आसानी से संप्रेषण में डाक सेवाओं की भूमिका को देखते हुए पोस्टकार्ड, मनीआर्डर, मुद्रित पुस्तकों वाले पुस्तक के पैकटों तथा पंजीकृत समाचार पत्रों के शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परन्तु, मुद्रित पोस्टकार्ड की दर 1.50 रुपए से बढ़ाकर 2.00 रुपए, प्रतियोगिता पोस्टकार्ड की दर 3.00 रुपए से बढ़ाकर 4.00 रुपए, अन्तर्देशीय पत्र 1.50 रुपए से बढ़ाकर 2.00 रुपए, प्रथम 50 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए पुस्तक के आकार के तथा छोटे पैकेट के लिए 1.00 रुपए से बढ़ाकर 2.00 रुपए, और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए 2.00 रुपए से बढ़ाकर 3.00 रुपए, और प्रत्येक 500 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए पार्सलों की दर 10.00 रुपए से बढ़ाकर 12.00 रुपए

और प्रत्येक अतिरिक्त 500 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए 10.00 रुपए से बढ़ाकर 15.00 रुपए की जा रही है। कुछ अन्य परिवर्तन भी किए जा रहे हैं जिन्हें बजट दस्तावेजों के साथ परिचालित ज्ञापन में बताया गया है। ये परिवर्तन वित्त विधेयक के पारित होने के बाद अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे। प्रस्तावित संशोधनों से पूर्ण वर्ष में लगभग 145 करोड़ रुपए और वर्ष 1999-2000 के दौरान लगभग 121 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस मामूली बढ़ोतरी से जो डाक सेवाओं के विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, डाक सेवाओं की लागत केवल आंशिक रूप से ही पूरी हो पाएगी।

115. मेरे कर प्रस्तावों तथा डाक शुल्कों में संशोधन के फलस्वरूप, केन्द्र सरकार के कुल व्यय में वर्ष 1999-2000 में मामूली गिरायट होकर यह 2,83,882 करोड़ रुपए हो जाएगी जबकि निवल राजस्व प्राप्तियां तथा ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां बढ़कर 2,03,927 करोड़ रुपए हो जाएंगी। राजस्व घाटा 54,147 करोड़ रुपए आंका गया है जबिक राजकोषीय घाटा 79,955 करोड़ रुपए आंका गया है। यह केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा घोषित सकल घरेलू उत्पाद की नयी शृंखला के आधार पर और राज्य सरकारों के संबंध में अल्प बचत संग्रहणों के भाग के भुगतान को शामिल न करने के बाद क्रमशः 2.7 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत बैठता है। सकल घरेलू उत्पाद की पुरानी शृंखला के आधार पर और इसी प्रकार राज्य सरकारों के लघु बचत संग्रहण के भाग के भुगतान को शामिल न करते हुए यह प्रतिशत क्रमशः 3.0 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत बनता है।

116. इस बजट के माध्यम से, हम अपनी अर्थव्यवस्था की राजकोषीय स्थित को बनाए रखने के लिए एक मध्याविक कार्यनीति प्रारंभ कर पायेंगे। इस बजट में राजस्व और राजकोषीय घाटे को सकल दरेलू उत्पाद के क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत तक नीचे लाने का प्रस्ताव है। इसमें कमी की मौजूदा दर से, राजस्व घाटे को 4 वर्षों में समाप्त कर दिया जाएगा तथा राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से नीचे आ जाएगा। बजट में हमारे उत्पाद करों में भारी सुधार करने का प्रस्ताव है। मध्याविध में, हम सकल दर तथा पूर्ण 'वैट' प्रणाली की ओर अग्रसर होंगे। हमारे सीमाशुल्क ढांचे को कम करके 5 वर्षों में एशियाई स्तरों पर लाया जाएगा। इस अविध के दौरान भारतीय उद्योग की पुनर्सरचना हो जाएगी तथा वह विश्व बाजारों के साथ पूर्णतया प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए सक्षम हो जाएगा। हमारे ज्ञान पर आधारित उद्योग कई लाख रोजगार पैदा करेंगे, प्रतिस्पर्द्धा तथा उत्पादकता में वृद्धि से प्राप्त लाभ हमारे निर्यात को नई कंचाइयों में ले जाएंगे। इसी अविध के दौरान, हमारी भौतिक तथा मानव अवसंरचना विश्व के स्तर तक पहुंचाई जानी चाहिए। इन सबके अलावा, हमारे सभी लोगों की खाद्य, आश्रय, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बुनियादी आवश्यकताएं अब से एक दशक के भीतर पूरी कर ली जाएंगी।

117. ये उपलब्धियां भारत को वर्ष 2020 तक वास्तविक रूप से एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करेंगी। इक्कीसवीं शताब्दी हमारी होगी।

118. प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में -

आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो,' राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस-जिस की हिम्मत हो॥

119. अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह बजट इस सम्माननीय सदन को प्रस्तुत करता हूँ।

जे. एस. माथुर, अपर सचिव (बजट)

PART B

- 58. Sir, I now present my tax proposals.
- 59. I will start with indirect taxes, with excise first. The multiple rates of indirect tax are generally recognised to be a major source of misclassification, tax evasion and avoidance and cumbersome litigation. The multiplicity also encourages inefficient allocation of resources. Over a 100 countries in the world now enjoy the benefits of a Value Added Tax (VAT) with very small number of rates in each case.
- 60. In my last Budget, I had clearly stated my resolve to rationalise the rate-structure so as to reduce the multiplicity of rates and ensure convergence towards a central rate with a merit rate and a demerit rate. Most of our major industry associations have also called for a triple rate excise structure.
- 61. My excise proposals today largely fulfil my intent announced 9 months ago. Specifically, I propose to reduce the existing 11 major ad valorem rates to 3, namely, a central rate of 16%, a merit rate of 8% and a demerit rate of 24%. To achieve this, I propose to:
 - * Merge the existing rates of 5%, 10% and 12% into the existing 8% rate;
 - * Create a new rate of 16% by merging the existing 13%, 15% and 18% rates into it; and
 - * Fix a new rate of 24% in substitution of the existing rate of 25%.

Honourable Members may notice that I have reduced the previously announced central rate of 18% to 16%. This means lower costs and prices. There is also a happy coincidence that this rate is almost identical to the rate of one-sixth (Shadbhaga) advised by Kautilya, the noble sage of Pataliputra, which also happens to be my birthplace.

- 62. Considerations of revenue in this difficult year, however, persuade me to fix 2 slabs of surcharge (special duty of excise) of 6% and 16% over the rate of 24% on commodities which today carry a rate of duty of 30% and 40%. Thus total excise on these commodities will remain unchanged. Petrol will continue to be taxed at 32%. The surcharge structure gives a clear indication that in future the Government would gradually phase them down to the demerit rate of 24%.
- 63. As a result of these changes the excise rates for many commodities will either come down, or remain unchanged or be adjusted marginally upwards by a 1% point. In the one major area of machinery and capital goods where the basic rate is rising from 13% to 16%, I must point out that excise on such products are eligible for MODVAT credit in the hands of the buyer. Furthermore, to help the capital goods sector, my customs duty proposals include removal of the long standing anomaly by which the duty rate on the major input, steel, is higher than the duty rate on finished capital goods. I must also emphasise that this major reform of the excise rate structure is broadly revenue neutral. It does not impose additional tax burden on industry as a whole. I am confident this major reform will stimulate productivity, growth and employment.
- 64. Mr. Speaker, Sir, I now move on to my next proposal. I propose to garner additional revenue by way of an additional duty on High Speed Diesel Oil (HSD). Currently, international and domestic prices of crude oil and petroleum products are unusually soft, and it is felt that raising some additional revenue through this commodity would be an equitable method of resource mobilisation. Therefore, I propose an additional duty of Re. 1 per litre on imported and domestic HSD, the revenue from which will accrue entirely to the Centre. Of this duty, I propose to allocate half to support the initiatives in rural development and social sectors. The other portion of 50 paise of this duty as also the duty of Re. 1 per litre levied with effect from 2.6.1998 will be converted into a statutory cess and transferred to the Central Road Fund. 30% of the Fund will be transferred to the State Governments for

development and maintenance of State Roads. The balance amount will be utilised for development and maintenance of National highways and expressways and by the Ministry of Railways for construction of Railways over-bridges and Railways safety works at unmanned Railways crossings. This will cover the gap in the plan resources of the Ministry of Railways for the year 1999-2000. It is estimated that we will be able to collect an aggregate amount of Rs.4,591 crore as additional duty of excise and Rs.363 crore as countervailing duty on domestically produced and imported HSD over the year. The Ministry of Petroleum & Natural Gas will announce consequential changes in the price of HSD effective from midnight tonight. This will also fulfil in a large measure the will of Parliament reflected in Resolution dated 13th May, 1988, which contemplated earmarking a portion of the excise and customs duties on petrol and diesel to raise resources for development of roads.

- 65. In the last budget the MODVAT adjustment allowed to manufacturing units had been capped at 95%. I propose to lift this cap on MODVAT claims and restore it to 100%.
- 66. Mr. Speaker, Sir, my budget proposals also contain a package for the Small Scale Industry (SSI) sector consisting of the following components:
 - * Under the specific excise duty concession schemes for units manufacturing cosmetics, refrigeration and airconditioning equipment, I propose doubling of the turnover under the eligibility criteria from Rs.50 lakh to Rs.100 lakh; doubling of the duty free exemption slab from Rs.15 lakh to Rs.30 lakh; and, an increase from Rs.15 lakh to Rs.20 lakh in the clearances eligible for duty at half the normal rates.
 - * I propose to extend the benefit of the SSI exemption limits to small-scale units producing cotton yarn.
 - * I propose to exempt small job workers engaged in printing of glazed tiles from the incidence of excise duty.
 - * Currently, SSI units are not eligible for exemption from excise duty on products bearing the brand name of another manufacturer. I propose to extend the SSI exemption to goods bearing a brand name of another manufacturer, when produced by units located in the rural areas. The details of the scheme will be announced shortly.

- 67. Under the current procedure, all manufacturing units are required to pay excise duty at the time of clearance of goods from their manufacturing premises. As a measure of further simplification of administrative procedures, I propose to permit SSI units to pay excise duty on a monthly basis with effect from 1.6.1999. Besides constituting a significant step in the simplification of procedures, this change will also improve the liquidity position of manufacturing units in the SSI Sector.
- 68. I am proposing a similar procedural relaxation in respect of the requirement of maintenance of excise records by factories. Henceforth, factories paying more than Rs.5 crore excise duty in a year, will not be required to maintain their records in a specific format prescribed by the excise department; and, the records maintained in the normal course of their functioning would be accepted as adequate. This amendment will take effect from 1.6.99.
- 69. Currently, there are several commodities, which are enjoying either total exemption from excise duty or are enjoying concessional excise duty. These concessions were sanctioned in the past with reference to the specific circumstances relating to that commodity prevailing at that point of time. With the lowering of general rate of duties, the need for such exemptions and concessions has abated. I propose to set up an Expert Committee to examine and advise on where the exemptions should be retained and where they should be integrated into the new rate structure. Their report should be available for consideration before the next budget.
- 70. As Hon'ble Members are aware, Government is empowered to grant exemptions from excise duty on an adhoc basis. I do not consider such wide discretion necessary. Hence, I propose to abolish Government's power to grant adhoc exemptions of excise duty except for goods of strategic nature, or for charitable purposes. I propose abolition of similar powers on the customs duty side also.
- 71. Mr. Speaker, Sir, I now turn to my proposals relating to customs duties. My proposals here reflect a balance of differing considerations. On the one hand, we are committed to a calibrated integration of our economy with the world economy. This would entail further phasing down of our customs duties to Asian levels. On the other hand, is the need to raise revenue and the fact that in a year of exceptional turbulence and uncertainty in the world

economy, our industry should be cushioned against unusual surges of competitive pressure from imports.

- 72. Sir, a special customs duty of 2% was imposed in the budget of 1996-97, and a further special customs duty of 3% was imposed on certain items in 1997-98. The special customs duty of 5% is in force till 31.3.1999. I have in the course of another discussion assured this House that the period of validity of this special customs duty will not be extended. I announce the discontinuance of the 5% special customs duty with effect from 28.2.1999.
- 73. After careful examination of various possibilities, and close interaction with the apex organisations of Commerce and Industry. I propose to reduce the existing 7 major ad-valorem rates of customs duty to 5 basic rates. The new rates will be:
 - 5% which will remain unchanged;
 - 15% by substituting the existing 10% rate;
 - 25% by merging the 20% and 25% rates;
 - 35% by merging the 30% and 35% rates:
 - 40% which will remain unchanged.
- 74. The one industry in which a special regime of customs duty will apply is the Information Technology sector. The Prime Minister has repeatedly emphasised the importance of this sector for the country's development in the new century and millennium. Accordingly, I am proposing significant reduction in duty rates of a number of critical inputs in this sector, such as ICs and micro assemblies, storage devices and CD Roms, telecom equipment and optical fibres.
- 75. To garner revenue to meet the country's irreducible needs, I propose a uniform surcharge of 10% on all commodities, excluding the following categories:
 - Crude Oil and Petroleum Products;
 - Items attracting 40% rate of basic duty;
 - Certain GATT- bound items:
 - Gold and Silver:

The effect of the surcharge would be to raise the basic rate by 10%. Thus a basic rate of 5% would become 5.5%, 15% would become 16.5% and so on.

- 76. Taking into account that special customs duty is being discontinued, and that crude oil and petroleum products are exempt from surcharge, the effective import duty rates on these products will stand reduced. This is consistent with the Government's established policy of rationalising indirect taxes on these products in an agreed time-frame.
- 77. By exempting items attracting 40% rate of basic duty from the surcharge, there is a modest but clear reduction in the peak rate of protective custom duty from 45% to 40%.
- 78. Mr. Speaker, Sir, conceptually, I am averse to zero custom duty, since our domestic industry generally merits some minimal protection. I have reviewed the entire list of such commodities and to begin with I am proposing the imposition of 5% rate of duty for some of these commodities. In order to mitigate the impact of the incidence of 5% rate of duty on such items which have previously enjoyed exemption, I propose to exempt this category from the existing 4% special additional duty.
- 79. I am rationalising the import duty structure of project imports. Under this rationalisation, power generation, coal mining, refinery, telecom and fertilizer projects will now attract a nominal basic customs duty of only 5%. However, they will be subject to applicable rates of countervailing duty. The net impact of these changes will not be significant in most cases. Mega Power Projects also will be an exception to this.
- 80. Mr. Speaker, Sir, as a result of the various proposals made in this budget on the indirect taxes, the estimated revenue in 1999-2000 would be Rs. 1,17,625 crore, including a component of net additional resource mobilisation of Rs. 6.234 crore.
- 81. Last year, I had announced the setting up of an Authority for Advance Rulings for Excise and Customs. The necessary legislation has been included in this Finance Bill. Drawn on the lines of the Advance Rulings Authority on the Direct Taxes, the proposed Authority would provide binding rulings on important issues, so that intending investors will have a clear-cut indication of their duty liability in advance.
- 82. The Central Board of Excise & Customs has adopted a "Vision Document" and the "Citizens Charter" which together present a blue print for the future and the service standards that can be expected of the Customs and Excise Department. The compliance of the service standards set out in the Charter is being closely monitored. The Commissioners of Customs and field level

officers have been directed to enhance the quality of their service and have also been told that any non-compliance would be viewed adversely.

- 83. On the central excise side, the computerisation of assessment and audit operations is being given focussed attention, and before long, electronic filing of returns is proposed to be put into operation.
- 84. Copies of the notifications giving effect to proposed changes in customs and excise duties will be laid on the Table of the House in due course.
- 85. Mr. Speaker, Sir, I now turn to the proposals on the direct tax side.
- 86. With growing liberalisation of the economy has come the need for industrial restructuring so that companies can focus better on their core activities. The corporate sector has been voicing the need for a flexible fiscal policy for regulating business reorganisations. In response to this need, I propose a comprehensive set of amendments to the Income Tax Act to make such business re-organisations fully tax neutral. In the case of amalgamation of companies, the existing requirement of routing the proposal through Board of Industrial and Financial Reconstruction is being removed. The legal provision is proposed to be amended so that the eligibility for tax concessions is only contingent upon a minimum of 75% of the fixed assets of the amalgamating company being absorbed in the amalgamated company, and subject to the condition that the amalgamated company will continue the business of the amalgamating company for a minimum of 5 years. An enabling provision will be provided through the amendment of the Income-Tax Act, for the detailed guidelines to be issued subsequently under the powers available from the statutory provision.
- 87. In the case of de-mergers, I propose to introduce a legal provision so as to permit the carry forward of accumulated losses and unabsorbed depreciation from the de-merging company to the resultant company. I also propose to amend the legal provisions so that, neither the companies involved, nor the shareholders, are subject to capital gains tax as a result of the transactions. Further, it is proposed that all fiscal concessions will survive for the unexpired period in the case of amalgamation and de-mergers
- 88. Mr. Speaker, Sir, Government has been greatly concerned about the persisting sluggishness in the capital markets.

Government is also distressed to note the negative perception of some sections of the investing public in regard to the schemes operated by the Unit Trust of India. Based on the recommendations of the Committee headed by Shri Deepak Parekh, and also taking into account a large number of suggestions offered by various experts in the field, I now propose a substantial fiscal package to restore the confidence of the shareholders in the UTI, and more generally to invigorate the capital markets.

- 89. First, I propose to fully exempt from income tax all income from UTI and other Mutual Funds received in the hands of the investors. This will not only reduce the incidence of tax, but will eliminate the inconvenience faced by small investors in paying tax and claiming refund in connection with income derived from such investments.
- 90. Presently if the income in the hands of the investors is fully exempt from tax, this income is subjected to dividend tax under Section 115 (O) of the Income Tax Act, at the stage of distribution of the dividend by UTI or mutual funds. As a departure from the policy, and as the second element of the package, I propose to continue for 3 years the exemption for US-64, Scheme as also for all open-ended equity-oriented schemes of UTI and mutual funds with more than 50% investment in equity from dividend tax. However, income distributed by Mutual Funds, where the equity investment is less than 50%, will become subject to the 10% dividend tax.
- 91. As a result of these two tax initiatives, investments in UTI and other Mutual Funds will become much more attractive and equity-oriented schemes will be relatively more attractive than schemes where equity investment is less than 50%. This should encourage the return of small investor to the capital market and revive confidence.
- 92. A complaint has often been voiced that there is discrimination between the rate of long-term capital gains tax on transfer of shares and securities as between residents and non-residents. The current rate of long-term capital gains tax for resident Indians is 20% linked to a notional value of capital gains, computed with reference to a Cost of Inflation Index. However, the rate of long-term capital gains tax for non residents is only 10%. In response to this complaint, I now propose to amend the law so as to cap the long-term capital gains tax for resident Indians on transfer of shares and securities, at the 10% rate.

- 97. As the first element of this package, I propose that the interest on a loan for a self-occupied property be exempted from tax up to a ceiling of Rs.75,000, increased from the current ceiling of Rs.30,000. This concession will encourage middle class investors to take loans to purchase modest dwelling units of their own.
- 98. The second element of this incentive package relates to the scheme for housing projects for enjoying a tax holiday under Section 80IA of the Income Tax Act. The existing provision, interalia, requires that the built -up area of dwelling units should not exceed 1000 sq. feet. There have been many representations that in towns other than Mumbai and Delhi, the land cost is relatively less, and therefore, for the same capital expenditure investors can afford to purchase dwelling units of slightly larger areas. In view of this, it has been represented that the ceiling on built -up areas for dwelling units in approved projects be increased from 1000 sq. ft to 1500 sq. ft at all locations except Mumbai and Delhi. I propose to accept this suggestion and make suitable modifications in the law. This amendment in the scheme for treating housing projects as infrastructure will, I believe, also give a significant fillip to construction activities in the smaller towns.
- 99. For the construction activity to pick up any significant degree of momentum, it has to be ensured that housing finance companies stay financially viable. Currently, such housing finance companies are subject to tax on interest on loans, on accrual basis. In order to lessen the burden on such housing finance companies, I propose to amend the law so that the income of such companies will be taxable on actual basis, rather than accrual basis.
- 100. A significant number of individuals seeking accommodation in the major cities are the employees of the business sector. I feel that it is necessary to encourage the business sector to invest in housing for their employees so as to add to the net housing stock. In this spirit, I propose to increase the depreciation rate from 20% to 40% on new dwelling units purchased by the business sector for its employees.
- 101. This entire package of fiscal incentives for the housing construction sector will, I believe, be a powerful force for revival of the entire economy. The construction sector has very strong linkages with several other major sectors, notably steel and cement. A general upsurge in construction activities will not only increase the corpus of housing stock in the country, but will give a substantial fillip to industrial activity.

- 102. Apprehensions have been expressed in certain quarters regarding the incidence of a high level of Non Performing Assets (NPAs) in some of the banks. I am of the view that the banks should make every effort to clean up their books and to remove any misgivings, which may exist about the transparency of the accounts. To assist in this direction, Mr. Speaker, Sir, I propose to make tax deductible such amounts as are provided by banks as 'doubtful debts' subject to a maximum of 5% of the such aggregate 'doubtful debts', in any one year. This concession will be available for a period of 5 years for such 'doubtful debts' as are identified under the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India.
- 103. I propose to amend the law so that tax concession will be available to a loanee on interest payment to a co-operative bank on actual basis rather than accrual basis. This proposal will induce the loanees to make timely repayment of their interest liability in order to avail of the tax benefit, and correspondingly, the financial condition of the co-operative banks can be expected to improve.
- 104. Mr. Speaker, Sir, I now turn to the proposals relating to the Infrastructure and Industry sectors.
 - * I propose to extend the fiscal incentives by way of the tax holiday under Section 80 IA of the Income Tax Act, to cold chains for agricultural produce.
 - The financial condition of most of State Electricity Boards is extremely precarious. Many of the State Electricity Boards wish to remedy the situation by unbundling generation, transmission and distribution activities to separate companies. I propose to treat the activities of transmission and distribution of power, set up after 1.4.1999, as eligible activities for fiscal incentives available to infrastructure units. I am sanguine that this proposal will facilitate the restructuring and rehabilitation of the State Electricity Boards.
 - * Currently, the tax exemption given under Section 80 IA of the Income Tax Act to the infrastructure sector and other core sectors, has to be availed of within a given maximum period. This given maximum period has come to vary from sector to sector. In order to bring about uniformity, I propose the amendment of the Income Tax Act so as to provide a maximum period of 15 years in which units can avail of the tax concessions offered to infrastructure and other core sector units.

- * Mr. Speaker, Sir, I am conscious of the fact that, despite all our announcements, the industrial development in North Eastern Region has not come up to our expectations. To give industrialisation a fillip in this area of the country, I propose a 10 year tax holiday for all industries set up in Growth Centres, Industrial Infrastructure Development Corporations, and for other specified industries, in the North Eastern Region. I would urge the industrial entrepreneurs from this part of the country to seize the opportunity and set up modern, high value added manufacturing units in the region.
- 105. The Indian entertainment industry, which includes films, music and television software is growing by leaps and bounds. I believe that with our creativity and our talent, India has the potential to become a global media superpower. We have done remarkably well in the field of computer software development and exports, and the same can be achieved in the development and export entertainment industry products, specially films, TV, software and music. With a view to facilitating India becoming a super power in this sector, I am including a number of measures in the budget. My aim is to give similar facilities and tax benefits to this sector as are available to the export of goods and merchandise under section 80HHC.
- 106. Let me assure you that it would be our endeavour to support the entertainment industry "Dil Se", and I am sure that no longer would the industry have to ask the government "Hum Apke Hain Kaun"?
- 107. Mr. Speaker, Sir, we are all conscious of the fact that the Information Technology sector is going to be the sector of the future. The immediate crisis, which is looming over this sector, is connected with the Y2K Problem, which will hit us at the close of the current calendar year. I get the impression that the corporate sector is not adequately seized of the dangers which lie ahead on account of this problem. In these circumstances, to assist the business sector to overcome the Y2K Problem, I propose that all expenditure incurred in making their systems Y2K compliant be allowed as revenue expenditure in the next financial year. I urge the business sector to avail of this concession and make every effort to remedy the defect in their software systems, so that their valuable databases do not spin into chaos.
- 108. Under the current law, a weighted deduction of 125% of the expenditure made on in-house R&D is available to corporate

houses up to 31.3.2000. Representations have been received that this period is too short for any company to plan its R&D programme. I propose to extend the concession for in-house R&D up to 31.3.2005. Further, I propose to extend a similar concession of permitting a weighted deduction of 125% of expenditure for R&D Projects entrusted to research laboratories and universities. In the globalised economy, the future is for those who are in the vanguard of development of technology. In view of this, I would urge the corporate sector to avail of this facility to the fullest extent.

- 109. In the last few years, the direct tax department has undertaken a concerted drive to extend the national tax base. As a method of identifying potential taxpayers, the "One by Six" scheme was extended to 35 cities in 1998-99. This Scheme has given very satisfying results. Consequent upon the launching of this scheme, the number of tax assessees has risen from 120 lakh to 140 lakh in the period of one year. It is the assessment of the department that there is considerable scope for further registration of tax assessees. In view of the favourable results of the scheme, I now propose to extend this scheme to 19 more cities in the country having a population of more than 5 lakh.
- 110. Since the last budget, the Income Tax department has undertaken a drive for issue of PAN Numbers to the tax-paying applicants. The response of this scheme has been overwhelming, and we have received as many as 168 lakh applications. The requisite PAN Numbers have already been issued to 75 lakh taxpayers and we are confident that the remaining applications will be disposed in the next few months.
- 111. Mr. Speaker, Sir, I will now like to highlight the proposals which are targeted at those sections of society which require Government's special attention. First, I propose that the deduction for medical insurance premia for senior citizens be raised from the current level of Rs. 10,000 to Rs. 15,000 and tax deduction for treatment of specific diseases be increased to Rs. 60,000. Considering the fact that medical and hospitalisation costs have risen and life expectancy has also improved, the general insurance industry intends to increase the upper ceiling of the sum insured under the mediclaim policy from the existing level of Rs. 3 lakh to Rs. 5 lakh, and the upper age limit for coverage to 80 years from the existing 75 years. Second, I propose that expenditure made in respect of hostel projects for working women be eligible for deduction from taxable income under Section 35AC of the Income-Tax Act. Third, I propose that pension received by the recipients

of the different gallantry award winners, and the family pension received by their heirs, be exempted from income tax.

- 112. Mr. Speaker, Sir, I now submit my last proposal on direct taxes. I face the difficult task of containing the revenue and fiscal deficits on the one hand, and on the other meeting the growing development expenditure. I propose to fulfil this task and also ensure equitable burden sharing. I am making a modest demand only on those sections of our society who have the capacity to pay while exempting low-income earners. With these considerations, I propose to impose an across-the-board surcharge of 10% on Corporate Tax, and also a 10% surcharge on all other categories of assessees. In respect of individuals and Hindu Undivided Families, the applicability of the surcharge is limited to those having total income of Rs.60,000 or more. In effect, this surcharge will mean an increase of a marginal 2% in the 20% slab & 3% in the 30% slab. It would leave the rate in the 10% slab unchanged. This is in the nature of a temporary surcharge. I trust that the House and our citizens will appreciate the circumstances in which I have had to make this proposal.
- 113. To sum up, Mr. Speaker, Sir, as a result of the various proposals made in this budget on the direct taxes, the estimated revenue in 1999-2000 would be Rs.59,235 crore, including a component of net additional resource mobilisation of Rs.3,100 crore.
- 114. I now have something to say on behalf of my colleague, the Minister of Communications. Postal Service is highly employment intensive and salary & allowances constitute a major part of the operating expenses of the Postal Department. A revision of tariff for some postal services has, therefore, become unavoidable. However, in the interest of the common man and the role of the postal services in easy dissemination of news and information there will be no change in the tariff for Postcard, Money orders, Book packets containing printed books and Registered newspapers. However, the rate of Printed Postcard is being raised from Rs.1.50 to Rs.2.00, of Competition Postcard from Rs.3.00 to Rs.4.00, of Inland letter from Rs.1.50 to Rs.2.00, of Book pattern and sample packets from Re.1.00 to Rs.2.00 for first 50 grams or part thereof and from Rs.2.00 to Rs.3.00 for every additional 50 grams or part thereof, and Parcels from Rs.10.00 to Rs.12.00 for a weight not exceeding 500 grams or part thereof and from Rs. 10.00 to Rs. 15.00 for every additional 500 grams or part thereof. There are also certain other changes, which are explained in the

Memorandum circulated along with the budget documents. The changes would take effect from a date to be notified after the Finance Bill is passed. The revisions proposed are estimated to yield additional revenue of about Rs.145 crore in a full year and about Rs.121 crore during 1999-2000. Even this modest increase which is necessary for sustaining postal development, will only partially meet the cost of various services.

- of the Central Government for the year 1999-2000 would be marginally reduced to Rs.2,83,882 crore while with my tax and other proposals, net revenue receipts and non-debt capital receipts would increase to Rs.2,03,927 crore. The revenue deficit is placed at Rs.54,147 crore, while the fiscal deficit is placed at Rs.79,955 crore. This amounts to 2.7% and 4.0% respectively on the basis of the new series of GDP announced by Central Statistical Organisation and after excluding the payment of the share of small savings collection to State Governments. Based on the old series of GDP and excluding the payment of the share of small savings collection to State Governments, the percentage works out to 3.0% and 4.4% respectively.
- 116. With the Budget for 1999-2000, we will have set in motion a medium-term strategy for restoring the fiscal health of our economy. This budget proposes to reduce the revenue and fiscal deficits by 0.7% and 0.6% of GDP, respectively. At this rate of reduction, the revenue deficit will be eliminated in 4 years and the fiscal deficit will have declined below 2% of GDP. The budget proposes major reform of our excise taxes. In the medium-term we will move to a single rate and a full-fledged VAT system. Our customs duty structure will be phased down to Asian levels in 5 years. During this period Indian industry will have restructured and become fully competitive in world markets. Our knowledgebased industries will generate lakhs of jobs. The gains from competition and productivity growth will drive our exports to new heights. Over the same period our physical and human infrastructure will be raised close to world class. Above all, the basic needs of all our people for food, shelter, health, education and employment will be met within a decade from now.
- 117. These achievements will transform India into a genuine economic super power by the year 2020. The twenty-first century belongs to us.

118. In the words of the Prime Minister Shri Atal Behari Vajpayee -

आँखों में यैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्यार न रुकता, आए जिस-जिस की हिम्मत हो॥

With dreams of prosperity and marching at a stormy pace, the tide of patriotism will not recede. Let the courageous come forward to join me.

119. Mr. Speaker, Sir, with these words, I commend the budget to this august House.

J. S. MATHUR, Addl. Secy. (Budget)